A Daily News Magazine
भोपाल
बुधवार, 08 जुलाई, 2026

सुबह सवेरे

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित
वर्ष 23, अंक 306, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

'क्यों' का सवाल छोड़ते ही विज्ञान ने अपनी आत्मा खो दी है...

प्रणव शर्मा एवं अर्चना शर्मा

यह एक गहरी और शायद बेचैन कर देने वाली बात है कि आज हम तकनीक पर अपनी महारत के सबसे ऊंचे मुक़ाम पर खड़े हैं, और ठीक उसी वक्त हमारा इंसानी एहसास पहले से ज़्यादा ग़रीब होता जा रहा है। यह महसूस होता है कि असली बदलाव उन औजारों में नहीं आया, जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उस इंसान में आया है जो हम बनते जा रहे हैं। सदियों तक विज्ञान को इंसानी आज़ादी की सबसे बड़ी मिसाल माना गया- अंधविश्वास के अंधेरे के खिलाफ़ एक बगावत। अपने सबसे साफ़ रूप में यह अनंत को समझने की एक कोशिश थी।

धीरे-धीरे, और लगभग बिना महसूस किए, हम उस दुनिया से निकल आए, जहां विज्ञान इंसान की तरक्की का जरिया था, और एक ऐसी दुनिया में आ पहुंचे हैं जहां इंसान को सिर्फ़ एक जैविक इकाई माना जाता है, जिसे एक बंद व्यवस्था के भीतर बेहतर बनाया जाना है। नई खोजों की आवाज़ अब एल्गोरिद्म के शोर में दब जाती है। सवाल अब यह नहीं रहा कि हम क्या बना रहे हैं। असली सवाल- जिसे हम बार-बार पूछने से बचते हैं- यह है कि यह सब बनाते-बनाते हम ख़ुद क्या बनते जा रहे हैं।

जब हम 'बिग डेटा' और 'न्यूरल नेटवर्क' की बात करते हैं, तो असल में हम एक बेहद डरावनी सच्चाई को नए और नरम अल्फ़ाज़ में बयान कर रहे होते हैं- यह सोच कि इंसान की पूरी रूह बस एक सीमित डेटा-सेट है। अगर कोई मशीन आंकड़ों के आधार पर यह तय कर सकती है कि कोई शख़्स क्या ख़रीदेगा, किसे वोट देगा, गम में कैसे टूटेगा या उकसावे पर क्या करेगा, तो फिर इंसान के भीतर मौजूद राज़ की कोई गुंजाइश नहीं बचती। समाज-वैज्ञानिक एरिख फ्रॉम ने कंप्यूटर के दौर की शुरुआत में कहा था कि पहले का ख़तरा यह था कि इंसान ग़ुलाम बन जाएगा, लेकिन आगे का ख़तरा यह है कि इंसान ख़ुद रोबोट बन जाएगा। रोबोट काम करता है, पर जीता नहीं। जबकि इंसान का किरदार तो उन्हीं मुश्किलों और टकरावों से बनता है।

यह स्थिति अचानक नहीं आई। यह बरसों में, छोटी-छोटी रियायतों से जमा हुई। हमने अपना ध्यान सोशल मीडिया की फ़ीड को सौंप दिया। अपनी याददाश्त सर्च इंजन के हवाले कर दी। अपनी तन्हाई नोटिफ़िकेशन के हवाले कर दी। इस मशीनी सोच का गहरा असर समाज में विज्ञान के किरदार पर, और उस समाज पर भी पड़ रहा है, जिसकी ख़िदमत विज्ञान अपने बेहतरीन रूप में हमेशा करता आया है। बीसवीं सदी के दरमियान विज्ञान को एक चारित्रिक प्रवास माना जाता था- जिसका ताल्लुक़ जर्मन परंपरा के उस ख़याल से था जिसे Bildung कहते हैं: यानी मुश्किल, ख़ूबसूरती और असली दुनिया की रुकावटों से गुजरकर इंसान का ख़ुद को गढ़ना। विज्ञान सीखना सिर्फ़ कोई तकनीक हासिल करना नहीं था। यह ख़ुद को बदल डालने का अमल था। विज्ञान इंसान को गढ़ने का एक स्कूल था।

आज विज्ञान को धीरे-धीरे एक ऐसी मशीन बना दिया गया है जो सवाल ठीक से पूछे जाने से पहले ही जवाब दे देती है। वैज्ञानिक मिज़ाज- यानी सवाल पूछने, शक करने और अपनी ग़लती मान लेने का हौसला- अब उस तकनीकी घमंड से बदला जा रहा है जिसका बस एक ही मक़सद बचा है: समाज का बे-रुकावट चलते रहना।

इस बदलाव की जड़ यह है कि हमने अपने वजूद से जुड़े सवालों से ही मुंह मोड़ लिया है। आज के दौर में हम उस मुक़ाम तक पहुंच गए हैं जिसे Wired पत्रिका में लिखते हुए विचारक क्रिस एंडरसन ने 'थ्योरी का ख़ात्मा' कहा था। अगर कोई एल्गोरिद्म लाखों-करोड़ों आंकड़ों के बीच कोई रिश्ता ढूंढकर निन्यानवे फ़ीसद सटीकता से नतीजा बता सकता है, तो 'क्यों' पूछना एक ऐसी फ़िज़ूलख़र्ची लगने लगती है जो हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। हम दुनिया को एक ब्लैक-बॉक्स की तरह देखने लगे हैं - नतीजा मान लेते हैं, यह समझने की जहमत उठाए बगैर कि वह कैसे आया। यह विज्ञान नहीं है। यह एक बारीक क़िस्म की भविष्यवाणी है, और हर भविष्यवाणी की तरह यह इतनी बार सही साबित हो जाती है कि हम भूल ही जाते हैं कि हमने पूछना कब का छोड़ दिया।

आज यह हमारी रोज़मर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हमने यह मान लिया है कि हम बस इन्फ़ॉर्मेशन-प्रोसेसिंग यूनिट हैं, जिन्हें अपडेट और ठीक किया जा सकता है, और एक अच्छी ज़िंदगी का मतलब है हर तरह की कमज़ोरी ख़त्म करना, हर उतार-चढ़ाव को सपाट कर देना, नतीजे को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाना।

न्यूरोसाइंटिस्ट स्टुअर्ट फ़ायरस्टीन का कहना है कि विज्ञान असल में जानकारी की तलाश नहीं, बल्कि नादानी की तलाश है- एक जिंदा, जरखेज, तखलीकी रिश्ता उस चीज़ से, जो अभी मालूम नहीं। एल्गोरिद्म इस मायने में नादान नहीं हो सकता। वह सिर्फ़ उसी दायरे में काम कर सकता है जिसे पहले से 'मसला' तय कर दिया गया हो। इंसान वैज्ञानिक, इसके उलट, तय मसले से नज़र उठाकर देख सकता है कि उससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प सवाल ठीक उसकी हद के बाहर मौजूद है। असली टकराव इंसानपरस्त और मशीन जैसी सोच के दरमियान है। इंसानपरस्त मानता है कि इंसानी तजुर्बा इतना पेचीदा है कि उसे पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता- इंसान के अंदरूनी वजूद की एक हक़ीक़त है, और हर हालत का अपना ख़ास वज़न है। अगर विज्ञान की असली तहज़ीब को, और उस बड़ी इंसानी तहज़ीब को बचाना है जिसकी ख़िदमत विज्ञान अपने बेहतरीन रूप में हमेशा करता आया है, तो हमें उस चीज़ को दुबारा हासिल करना होगा जिसे हम 'रूह' कह सकते हैं। गणितज्ञ रॉजर पेनरोज़ ने तक़रीबन तीन दहाइयों की मेहनत में यह दलील दी है कि इंसानी रियाजी की समझ में एक ऐसा हिस्सा मौजूद है, जिसे कंप्यूटर की ज़बान में नहीं समझाया जा सकता। अगर पेनरोज़ की बात थोड़ी भी सही है, तो इंसानी फ़ैसले की जगह एल्गोरिद्मी फ़ैसले को पूरी तरह अपना लेना सिर्फ़ एक तहज़ीबी नुक़सान नहीं होगा- यह एक इल्मी नुक़सान भी होगा: उन सच्चाइयों के दायरे का सिमट जाना जिन तक पहुँचा जा सकता है, और समझ के उन तरीक़ों का बंद हो जाना जो तारीख़ी तौर पर सबसे जरखेज रहे हैं। इसलिए हमें एक ऐसी साइंस तालीम और वैज्ञानिक तहज़ीब की वक़ालत करनी चाहिए जो 'बेइंतहा' को 'फ़ायदेमंद' पर तरजीह दे- इसलिए नहीं कि फ़ायदेमंद होना ग़ैर-ज़रूरी है, बल्कि इसलिए कि जो विज्ञान बेइंतहा को भूल चुका है, वह यह भी भूल चुका है कि उसकी शुरुआत क्यों हुई थी।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

पीएम मोदी का इंडोनेशिया से चीन को कड़ा मैसेज

● पीएम ने कहा-भारत स्वतंत्र इंडो-पैसिफिक का है बड़ा समर्थक

इंडोनेशियाई राष्ट्रपति बोले- मैं मोदी का करियर कॉपी करता हूं

जकार्ता (एजेंसी)। पीएम मोदी ने कहा, भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति का पक्षधर है। सभी देश अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करें और समुद्री रास्ते सभी के लिए खुले रहें। मोदी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों को लेकर कई देशों की चिंता बढ़ी हुई है। उधर, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा, मैं आपका करियर कॉपी करता हूं। उनके इतना कहते ही तालियां बजने लगीं। उन्होंने कहा, मोदी सरकार की कई योजनाएं सफल रही हैं। इसलिए वे इन्हें अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा हुआ इन योजनाओं पर कॉपीराइट नहीं है। भारत-इंडोनेशिया के बीच 20 समझौते हुए।

भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा इंडोनेशिया- भारत-इंडोनेशिया के बीच मंगलवार को जकार्ता में 20 समझौते हुए। सबसे अहम ब्रह्मोस डील रही। इसको लेकर दोनों देशों के बीच पिछले 4 महीने से बातचीत चल रही थी। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की अतिरिक्त यूनिट देगा। इसी के साथ फिलीपींस, वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बन गया है। इंडोनेशिया ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल भारतीय अस्त्र एयर-टू-एयर मिसाइल खरीदने का भी फैसला किया है। वहीं भारत इंडोनेशिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विकसित करने में भी मदद करेगा।

- **गुजरात का पटोला वस्त्र इंडोनेशिया में सम्मान का प्रतीक**- भारत के पश्चिमी छोर स्थित गुजरात मेरा गृहराज्य है। सदियों पहले गुजरात से कुछ गुजराती और सूफी संत समुद्र के रास्ते ही इंडोनेशिया आए थे। आज भी गुजरात के पटोला वस्त्र यहां सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रतीक हैं। इंडोनेशिया और भारत के लोग रद्र और संस्कृति से संबंधों से जुड़े हैं। हम लोगों ने लंबे समय तक विदेशी शासन का सामना किया है। हम दोनों ही राष्ट्र लगभग एक ही समय स्वतंत्र हुए। जब स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर संप्रभुता की बात आई तो भारत यूएन में इंडोनेशिया की संप्रभुता के लिए मजबूत आवाज बना। एक और बात जो हमें एक-दूसरे के करीब लाती है। वह है लोकंत्र और लोकतंत्र में विभिन्नता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।
- **भारत और इंडोनेशिया के लिए समुद्र एक सेतु है**- हमारी राजधानियां भले ही हजारों किमी दूर हों, लेकिन समुद्र में हमारे बीच 150 किमी की ही दूरी है। दूसरे देशो में भले ही समुद्र दूरी का कारण रहा है, लिए भारत इंडोनेशिया के लिए समुद्र एक सेतु है। उन्होंने कहा कि आज भारत और इंडोनेशिया एक साथ खड़े हैं।

डीएमके में आ जाओ 100 करोड़ ले जाओ

● टीवीके विधायक का दावा, मना करने पर मिली जान से मारने की धमकी

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु में सियासी घमासान के बीच टीवीके विधायक जी. सरवनन ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ डीएमके में शामिल होने के लिए उन्हें करोड़ों रुपये का लालच दिया गया और इनकार करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु के श्रीवैकुंटम विधानसभा क्षेत्र से टीवीके विधायक जी. सरवनन ने आरोप लगाया है कि उन्हें डीएमके में शामिल होने के लिए 30 करोड़, 50 करोड़ और यहां तक कि 100 करोड़ रुपये तक का प्रस्ताव दिया गया। टीवीके विधायक जी. सरवनन ने दावा किया, कई लोग सीधे मेरे पास आए और कहा कि हम आपको 30 करोड़, 50 करोड़, यहां तक कि 100 करोड़ रुपये तक देंगे। बस आप डीएमके में शामिल हो जाइए। लेकिन जब मैंने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो उन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया और खुलेआम जान से मारने की धमकियां दीं। उन्होंने कहा कि अगर मैंने उनकी बात

नहीं मानी तो मुझे खत्म कर दिया जाएगा। सरवनन ने कहा कि उन्हें धमकी दी गई कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो उनकी गाड़ी में ट्रक से टक्कर कराकर उनकी हत्या कर दी जाएगी।

सुप्रभात

'एक रात वे सूचना देते हैं-
बीमा करा लिया है

वे बच्चों को प्यार करना चाहते हैं
लेकिन अनायास ही वे
बच्चों को डाँटने लगते हैं

कभी-कभी वे नाकुछ
बात पर ठहाका लगाते हैं
हम देखते हैं उनके दाँत
पीले पड़ने लगे हैं

धीरे-धीरे झुर्रियाँ उन्हें घेर लेती हैं
वे अपनी ही खंदकों,
अपने ही बीहड़ों में
छिपना चाहते हैं

यकायक वे किसी कंदरा,
किसी तंद्रा में चले जाते हैं
और किसी को भी पहचानने से
इंकार कर देते हैं।'

- कुमार अंबुज

लियूगोंग इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शुभारंभ आज

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पीथमपुर में करेंगे इसका शुभारंभ

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार 8 जुलाई को धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि-पूजन करेंगे। चीन की अग्रणी बहुराष्ट्रीय निर्माण उपकरण निर्माता कंपनी गुआंग्शी लियुगोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड की भारतीय इकाई द्वारा किया जा रहा यह विस्तार मध्यप्रदेश को निर्माण उपकरण विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। पीथमपुर में स्थापित होने वाला नया संयंत्र लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना में लगभग 2.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जा रहा है। संयंत्र में प्रारंभिक चरण में प्रतिवर्ष 6,500 निर्माण उपकरणों के उत्पादन की क्षमता विकसित की जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से एक्सकेवेटर का निर्माण किया जाएगा। इससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलने के साथ आयात पर निर्भरता कम होगी तथा क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

परियोजना 20 एकड़ क्षेत्र में होगी विकसित, बड़ा होगा निवेश

लियुगोंग विश्व की अग्रणी निर्माण उपकरण निर्माता कंपनी

लियुगोंग विश्व की अग्रणी निर्माण उपकरण निर्माता कंपनियों में शामिल है तथा व्हील लोडर निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी पहचान रखती है। कंपनी व्हील लोडर, एक्सकेवेटर, मोटर ग्रेडर, माइनिंग डंप ट्रक, बुलडोजर, स्किड-स्टियर लोडर, फोर्कलिफ्ट, कोल्ड प्लेनर तथा अन्य आधुनिक निर्माण एवं खनन उपकरणों का निर्माण करती है। कंपनी वर्ष 2008 से पीथमपुर में अपनी विनिर्माण इकाई का संचालन कर रही है। 44 एकड़ से अधिक क्षेत्र में स्थापित इस संयंत्र में प्रतिवर्ष 3 हजार व्हील लोडर एवं मोटर ग्रेडर के निर्माण की क्षमता है। वर्ष 2009 में इसी इकाई से पहला मेड इन इंडिया व्हील लोडर तैयार किया गया था।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की।

सिया ने प्रेमी चेतन से कर ली थी चुपके से शादी

● केतन अग्रवाल मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा ● पुलिस सिया गोयल के दो दोस्तों से कर रही पूछताछ

पुणे (एजेंसी)। महाराष्ट्र के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में अब तक सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार केतन की मंगेतर सिया गोयल ने चार महीने पहले ही बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी से शादी कर ली थी। केतन की हत्या के आरोप में सिया और चेतन चौधरी जहां जेल में बंद हैं तो वहीं दूसरी ओर पुलिस अब और कड़ियां जोड़ने में जुटी है, ताकि इस मामले को और पुख्ता किया जा सके। पुलिस सिया गोयल के दो कॉलेज दोस्तों से पूछताछ कर रही है। इस मामले की जांच पुणे ग्रामीण पुलिस की लोनावाला थाना पुलिस कर रही है। जांच को

एसपी ग्रामीण खुद सुपरवाइज कर रहे हैं। केतन के पिता के आग्रह पर सरकार ने इस मामले में उज्जवल निकम को सरकारी वकील नियुक्त किया है।

केतन अग्रवाल केस में नया ट्विस्ट- पुलिस सूत्रों के अनुसार इन दोस्तों ने कथित तौर पर मैरिज रजिस्ट्री के लिए गवाह के तौर पर दस्तखत किए थे। सूत्रों का कहना है कि पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल से सगाई के बाद सिया गोयल ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी से चुपके से शादी कर ली थी। 20 साल की सिया गोयल और 25 साल की अग्रवाल की शादी नवंबर में तय हुई थी। 18 जून को पुणे के लोहागढ़ किले से गिरने के कारण केतन अग्रवाल की मौत हो गई थी। पुलिस का आरोप है कि यह सिया गोयल की रची हुई साजिश थी क्योंकि वह शादी नहीं करना चाहती थी।

रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी

पुणे ग्रामीण पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चौधरी ने चार महीने पहले एक स्थानीय रजिस्ट्रार ऑफिस में चुपके से शादी की थी। सूत्रों ने बताया कि गोयल के कॉलेज के दो दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है, जिन्होंने कथित तौर पर गवाह के तौर पर साइन किए थे। पुलिस इस बात की पुष्टि कर रही है कि क्या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोई मैरिज सर्टिफिकेट है, ताकि यह पक्का हो सके कि उन्होंने सच में शादी की थी। जिससे अग्रवाल के साथ फरवरी में हुई उनकी सगाई अमान्य हो गई। अगर यह एंगल जुड़ने से केस में नया मोड़ आ गया है।

इंस्टाग्राम पर रखी थी शादी की तस्वीर!

पुणे के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की मुलाकात सिया गोयल से परिवार के जरिए हुई थी और फरवरी में उनकी सगाई हुई थी। नवंबर में शानदार शादी के लिए उदयपुर में एक होटल बुक किया गया था। पुलिस की टेक्निकल टीमें एक प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट से डिलीट की गई फोटो रिकवर करने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें कथित तौर पर आरोपी जोड़े को शादी की माला पहने हुए दिखाया गया था। पुलिस चौधरी के बैंक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। पुलिस को जानकारी मिली है कि उसने सीक्रेट शादी को जल्दी निपटाने के लिए जरूरी पब्लिक नोटिस से बचने के लिए किसी बिचौलिए को पैसे दिए थे। कोर्ट ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c

न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ बुधवार, 08 जुलाई 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया 'प्रगति' प्रोजेक्ट, 20 हजार कृषि-उद्यमी और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाने का संकल्प

विकसित भारत बिना विकसित कृषि और समृद्ध गांव संभव नहीं : शिवराज

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को 'प्रगति' नामक एक राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य 20 हजार ग्रामीण युवाओं को कृषि-उद्यमी बनाकर देशभर के 20 लाख छोटे और सीमांत किसानों की आय, उत्पादकता और आजीविका में व्यापक सुधार लाना है। यह बहु-साझेदार पहल भारत में समावेशी, टिकाऊ और जलवायु-संवेदनशील कृषि परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

अपने संबोधन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत का सपना विकसित कृषि और समृद्ध गांवों के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि लागत घटाकर किसानों की आय बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और कृषि को लाभकारी बनाना है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि छोटे जोत वाले किसानों के लिए पारंपरिक खेती पर्याप्त

नहीं है, इसलिए वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग और कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देना जरूरी है। उन्होंने बताया कि 'प्रगति' इसी सोच का विस्तार है, जो किसानों को तकनीक, मशीनीकरण, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और बाजार से जोड़कर उनकी वास्तविक आय बढ़ाने का रास्ता तैयार करेगा।

यह पहल देश के प्रमुख कृषि राज्यों- मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड में लागू की जाएगी। कार्यक्रम के तहत तैयार किए जाने वाले कृषि-उद्यमी गांव स्तर पर सलाह, मिट्टी परीक्षण, मशीन सेवाएं, वित्तीय लिंक, बाजार कनेक्ट और वैकल्पिक आय के अवसर उपलब्ध कराएंगे। श्री चौहान ने कहा कि केवल खेती करने से काम नहीं चलेगा, हमें वैल्यू एडिशन और विविधीकरण की ओर बढ़ना होगा- बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे क्षेत्रों से किसानों की आय में गुणात्मक वृद्धि संभव है। उन्होंने तकनीक के उपयोग, ड्रोन, डिजिटल सलाह और वैज्ञानिक खेती को भविष्य का आधार बताया।

कार्यक्रम में महिला भागीदारी को विशेष महत्व देते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि बड़ी संख्या में 'कृषि सखी' और महिला उद्यमी इस बदलाव की धुरी बनेंगी और एक-एक उद्यमी पूरे गांव की तस्वीर बदल सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 'प्रगति' केवल एक योजना नहीं, बल्कि परिवर्तन का संकल्प है। यह गांवों को आत्मनिर्भर, रोजगारयुक्त और सशक्त बनाने का माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा कि राज्यवार कृषि रोडमैप और वैज्ञानिक आधार पर फसल योजना के जरिए सरकार कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव की दिशा में काम कर रही है।

सरकारी राशन में लाखों रुपये की गड़बड़ी उजागर, तीन संचालकों पर केस दर्ज, स्टॉक में भी हेराफेरी

धार। जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ग्रामीणों के सरकारी राशन में हेराफेरी का बड़ा मामला सामने आया है। राशन वितरण में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया। कलेक्टर राजीव रंजन

मीणा के निर्देशन तथा एसडीएम विशाल धाकड़ और जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्रीराम बार्डे के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग की टीम ने संबंधित पंचायतों में पहुंचकर शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। जांच में राशन के स्टॉक में भारी गड़बड़ी सहित कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। खाद्य आपूर्ति विभाग की रिपोर्ट पर पुलिस ने तीन दुकान संचालकों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुनीता मसराम सहित विभागीय टीम की जांच में तीन प्रमुख मामले सामने आए।

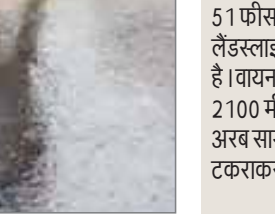

संक्षिप्त समाचार

बंगाल गैंगरेप मर्डर केस में 3 लोग गिरफ्तार

- बारूईपुर में जिंदा बच्ची तालाब में फेंकी थी

कोलकाता (एजेंसी)। बंगाल पुलिस ने सोमवार को दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में 12 साल की लड़की के रेप और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की

पहचान आनंद सरदार के तौर पर हुई है। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर उसे शहर के बाजार इलाके से पकड़ा। इसके साथ ही मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या तीन हो गई है। मामले की जांच के लिए 6 लोगों की टीम बनाई गई है। मासूम 4 जुलाई को लापता हुई थी। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि मासूम सहेली के लिए गिफ्ट खरीदने निकली थी। जब बच्ची घर नहीं लौटी तो परिवार ने शिकायत दर्ज कराई।

पति को ड्रिप में टॉयलेट क्लीनर डालकर मारा

- पत्नी नर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था

निजामाबाद (एजेंसी)। तेलंगाना में एक नर्स ने प्रेमी के साथ मिलकर 35 साल के पति की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, महिला ने 30 जून को पति को छत से धक्का देकर मारने की कोशिश की थी।

जब वह बच गया तो अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी नस में लगी ड्रिप में टॉयलेट क्लीनर इंजेक्ट कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी महिला 32 साल की संध्या, उसके प्रेमी अनिल और उसके दोस्त वेंकट साई को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि यह हत्या पहले से रची गई साजिश का हिस्सा थी, जिसकी वजह संध्या का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। यह पूरी घटना निजामाबाद जिले के मोपाल मंडल के न्यालाकल गांव की है। इसकी खबर सोमवार को सामने आई।

अहमदाबाद ब्लास्ट केस में 38 दोषियों की फांसी बरकरार

- 11 को उम्रकैद, 18 साल पहले 70 मिनट में 21 धमाके हुए थे

अहमदाबाद (एजेंसी)। गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में स्पेशल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। निचली अदालत ने फरवरी 2022 में 38 दोषियों को फांसी और 11 दोषियों को

उम्रकैद की सजा सुनाई थी। दोषियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। आज जस्टिस एवाई कोगजे और समीर दवे की बेंच ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर सभी अपीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े लोगों की सजा को सही ठहराया। कोर्ट ने सरकार को 56 मृतकों के परिजन को 10-10

वायनाड में टैंकर-गाड़ियां बहा ले गई सुरंग की मिट्टी

यह केरल का एकमात्र पठारी इलाका

वायनाड, केरल के नॉर्थ-ईस्ट में है। यह केरल का एकमात्र पठारी इलाका है। यानी मिट्टी, पत्थर और उसके ऊपर उगे पेड़-पौधों के ऊंचे-नीचे टीलों वाला इलाका। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक, केरल का 43 फीसदी इलाका लैंडस्लाइड प्रभावित है। वायनाड की 51 फीसदी जमीन पर पहाड़ी ढलाने हैं। यानी लैंडस्लाइड की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है। वायनाड का पठार वेस्टर्न घाट में 700 से 2100 मीटर की ऊंचाई पर है। मानसून की अरब सागर वाली ब्रांच देश के वेस्टर्न घाट से टकराकर ऊपर उठती है।

वायनाड (एजेंसी)। केरलम के वायनाड में मंगलवार सुबह तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग घायल हुए हैं। कई लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना है। हादसा कल्लाडी स्थित मीनाक्षी ब्रिज के पास हुआ। यहां मलप्पुरम-वायनाड टनल प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। टनल से मिट्टी निकालकर बाहर जमा की गई थी। बारिश के चलते मिट्टी खिसक गई, जिससे पेड़ उखड़ गए और बैरिकेड भी बह गए। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, इसमें दिख रहा है कि 7 जुलाई को सुबह 11 बजकर 15 मिनट पर सुरंग से तेज लहर के साथ आया मलबा एक टैंकर को तिनके की तरह बहाकर ले गया। दो लोग इसके मलबे में फंसे। पुलिस, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मलबा हटाने के लिए भारी मशीनों की जरूरत होगी। अधिकारियों के अनुसार, लगातार बारिश के कारण सोमवार से ही सुरंग कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया था। मलप्पुरम-वायनाड टनल प्रोजेक्ट के तहत मलप्पुरम को वायनाड से सुरंग (टनल) के जरिए जोड़ना है। दो साल पहले भी वायनाड में एक के बाद एक तीन भूस्खलन हुए थे, जिसमें 400 से ज्यादा जानें चली गई थीं।

2024 में सबसे बड़ा हादसा, 400 से ज्यादा की मौत- वायनाड में 2 साल पहले सबसे बड़ा लैंडस्लाइड हादसा हुआ था। 30 जुलाई 2024 रात करीब 2 बजे से 4 बजे के बीच मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा गांवों में लैंडस्लाइड हुईं।

चढ़ावा चोरी केस में मायावती ने चला अपना अलग दांव

बोलीं-सपा, कांग्रेस और एएपी सबूत दिखाएं वरना बंद करें ड्रामा

मायवती ने उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भी जांच की उठाई मांग

लखनऊ (एजेंसी)। अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी मामले पर बचे घमासान के बीच बीएसपी

की अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बड़े स्तर पर जांच की मांग उठाई है। मायावती ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि राम मंदिर और उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम मामले में मुख्य प्रबंधकों की भी सही से जांच होनी चाहिए। इसके अलावा मायावती एक बार फिर प्रदेश के विपक्षी दलों पर बरसी हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर दान चोरी मामले में अगर सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास सबूत हैं तो उन्हें सार्वजनिक करें, वरना ये सब राजनीति करना बंद करें। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, यूपी के अयोध्या में श्री राम मंदिर के बाद अब उत्तराखंड में भी बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे में चोरी और गबन आदि होने का मामला काफी सुर्खियों में है। मुख्य प्रबंधकों की भी सही से जांच होनी चाहिए।

खामेनेई की अंतिम यात्रा शियाओं के धार्मिक शहर कोम पहुंची

- जमकरान मस्जिद में जनाजे की नमाज हुई

तेहरान (एजेंसी)। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा मंगलवार को शियाओं के प्रमुख धार्मिक शहर कोम में निकाली जा रही है। तेहरान के बाद यहां भी लगातार दूसरे दिन लाखों लोग

उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं। खामेनेई और उनके परिवार के दिवंगत सदस्यों के ताबूत जमकरान मस्जिद लाए गए, जहां आयतुल्ला जवादी अमोली ने जनाजे की नमाज अदा कराई। मस्जिद परिसर और आसपास की सड़कों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। ड्रोन फुटेज में पूरा इलाका लोगों से खचाखच भरा दिखाई दिया। कोम शिया मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक केंद्र है। खामेनेई ने अपने शुरुआती धार्मिक जीवन में यहीं इस्लामी शिक्षा हासिल की थी।

पालतू कुत्ते के काटने पर मालिक को सजा, कोर्ट उठने तक कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना

जबलपुर। पड़ोसी के 8 वर्षीय बच्चे को पालतू कुत्ते के काटने के मामले में न्यायालय ने करीब छह साल बाद कुत्ते के मालिक को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) दीप्ती चौहान ने आरोपी को कोर्ट उठने तक के साधारण कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार, सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित कौशल्या अपार्टमेंट के पास रहने वाले सलीम रहमान 27 अक्टूबर 2020 को अपनी पंचर मोटरसाइकिल को पैदल मरम्मत के लिए ले जा रहे थे। उनका 8 वर्षीय बेटा अतौर रहीम रहमान पीछे-पीछे दौड़ रहा था। इसी दौरान पड़ोसी गैविन डिसूजा के पालतू कुत्ते ने बच्चे को काट लिया। घटना के बाद आरोपी के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जब बच्चे का इलाज कराने और कुत्ते को बांधकर रखने की बात कही गई तो गैविन डिसूजा ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।

सलीम रहमान ने घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 289, 294 और 506 (भाग-बी) के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया।

सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को धारा 294 और 506 (भाग-बी) के आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि, जानवर को लापरवाही से छोड़ने (धारा 289) के अपराध में दोषी मानते हुए कोर्ट उठने तक के कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एसडीओपी रवि कुमार मौर्य ने पैरवी की।

नीट यूजी एग्जाम में बहुत बड़ा बदलाव

2027 से 5-6 दिन में होगी यह परीक्षा

नई दिल्ली (एजेंसी)। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले के बाद इस परीक्षा में रिफॉर्म करने में जुटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अगले साल यानी 2027 में होने वाली नीट यूजी परीक्षा को लेकर कुछ बड़े बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 2027 में होने वाली नीट यूजी परीक्षा 5-6 दिन में आयोजित होगी। साथ ही एनटीए एग्जाम सेंटर्स में भी कमी करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, नीट यूजी 2027 एग्जाम पहली बार कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट आधारित होगा जो कि 500 शहरों में करीब 1000 सेंटर्स पर होगा। अभी तक यह परीक्षा 1 ही दिन लगभग 5 हजार सेंटर्स पर आयोजित होती थी।

हर दिन 5 लाख कैंडीडेट्स होंगे परीक्षा में शामिल- रिपोर्ट के अनुसार,

सूत्रों ने बताया है कि एनटीए 2027 से नीट यूजी परीक्षा को 5-6 दिन में आयोजित कराएगी और जिन सेंटर्स पर यह परीक्षा होगी उनमें मुख्य रूप से केंद्रीय विद्यालय जैसे सरकारी इंस्टीट्यूशन्स शामिल होंगे। हर दिन लगभग 5 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि एजेंसी बहुत जल्द इन बदलावों को लागू कर सकती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट के अलावा अन्य दूसरे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। सूत्रों ने बताया है कि अगले साल के नीट यूजी एग्जाम की प्लानिंग के मुताबिक, अधिकतर परीक्षा केंद्र केवी और नवोदय विद्यालय जैसे सरकारी स्कूल होंगे। एजेंसी की ओर से कुछ जाने-माने प्राइवेट संस्थानों को ही सेंटर बनाया जाएगा। एनटीए में प्रस्तावित बदलाव पूरा होने के बाद शिफ्ट टाइमिंग, टेस्ट शहरों की लिस्ट और दूसरी डिटेल्स के साथ एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है।

एनटीए में भी होंगे बदलाव!- एजेंसी से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि एनटीए के पूरे ऑर्गनाइजेशन को ऊपर से लेकर नीचे तक बदलने की तैयारी है। एजेंसी में यह काम इसी साल अक्टूबर से पहले पूरा किए जाने की उम्मीद है। एनटीए में लगभग 150 पोस्ट पर उम्मीदवारों का चयन होना है।

राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों का दिखा असर

सूत्रों ने यह भी बताया है कि यह जो बदलाव किए जा रहे हैं यह के राधाकृष्णन की अगुवाई वाली सात सदस्यों वाली हाई-पावर्ड कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है। इस कमेटी को केंद्र सरकार ने साल 2024 के पेपर लीक मामले के बाद गठित किया था। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले के बाद शिक्षा मंत्रालय ने सबसे पहले यह घोषणा कर दी थी कि अगले साल यानी 2027 से इस पेपर को पेन एंड पेपर मोड की जगह सीबीटी मोड में आयोजित किया जाएगा। यह फैसला भी राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही लिया गया था।

स्वास्थ्य संस्थाओं में दवाओं की समयबद्ध उपलब्धता जरूरी

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल बोले- सुनिश्चित की जाए अच्छी व्यवस्था

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में प्रदेश की मेडिकल सप्लाई चेन व्यवस्था की कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में आवश्यकता के अनुरूप गुणवत्तायुक्त दवाओं की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। दवाओं की मांग, भंडारण, गुणवत्ता परीक्षण, वितरण एवं मरीज तक वास्तविक उपलब्धता की पूरी प्रक्रिया को प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया जाए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि दवाओं की समय पर टेस्टिंग सुनिश्चित की जाए तथा गुणवत्ता परीक्षण उपरांत ही दवाओं का वितरण किया जाए। सभी स्तरों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रहे और डिमांड-सप्लाई गैप की स्थिति निर्मित न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि मरीजों को दवाओं का वितरण सहजता से हो तथा दवा उपलब्धता के संबंध में किसी भी स्तर पर अनावश्यक कठिनाई न आए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि तकनीक आधारित मेडिकल सप्लाई चेन व्यवस्था से दवाओं की उपलब्धता और वितरण की सतत निगरानी संभव होगी। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदाय की गुणवत्ता सुदृढ़ और अधिक प्रभावी होगी।

संभागीय मुख्यालयों पर 10 वेयरहाउस स्थापित किए जाएंगे

आयुक्त स्वास्थ्य धनराजू एस ने मेडिकल सप्लाई चेन व्यवस्था की प्रस्तावित कार्ययोजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर 10 वेयरहाउस स्थापित किए जाएंगे। इन वेयरहाउसों में दवाओं के सुरक्षित एवं व्यवस्थित भंडारण की व्यवस्था की जाएगी। हाई-एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का उपयोग कर दवाओं की रियल टाइम ट्रैकिंग तथा स्टॉक की स्थिति की सतत निगरानी की जाएगी। इससे मेडिकल सप्लाई चेन में एंड-टू-एंड इंटीग्रेशन सुनिश्चित होगा। दवाओं की उपलब्धता, स्टॉक की स्थिति, मांग एवं वितरण की जानकारी वास्तविक समय में प्राप्त हो सकेगी।

दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी

आयुक्त स्वास्थ्य श्री धनराजू एस ने बताया कि यह व्यवस्था क्षेत्रवार, केंद्रवार एवं स्वास्थ्य संस्था स्तर पर दवाओं की मांग का आकलन करने में भी सहायक होगी। इसके आधार पर आवश्यकता अनुरूप बेहतर योजना बनाते हुए दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। इससे अंतिम उपयोगकर्ता अर्थात मरीज तक गुणवत्तायुक्त दवाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी। मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दवाओं की खरीदी की जाएगी। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दवाएं वेयरहाउस तक पहुंचाई जाएंगी। वेयरहाउस में दवाओं का उचित भंडारण सुनिश्चित किया जाएगा और दवाओं की समय पर गुणवत्ता जांच कराई जाएगी। एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में परीक्षण उपरांत ही दवाओं को वितरण के लिए भेजा जाएगा। गुणवत्ता परीक्षण के बाद दवाओं का वितरण मेडिकल कॉलेजों, जिला चिकित्सालयों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों के औषधि भंडार, सिविल अस्पतालों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक किया जाएगा। आगामी चरण में इस व्यवस्था का एकीकरण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक किया जाएगा। साथ ही मरीज को दवा के वास्तविक वितरण की जानकारी भी रियल टाइम में दर्ज करने की व्यवस्था विकसित की जाएगी। बैठक में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्री मयंक अग्रवाल सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल की महिला डॉक्टरों ने कर दिया कमाल

गर्भवती महिला के पेट से निकला 10.2 किलो का ट्यूमर और 2.6 किलो का बच्चा

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में उस वक्त डॉक्टरों की सांसें थम गईं, जब एक बेहद नाजुक और रोंगटे खड़े कर देने वाली सर्जरी शुरू हुई। डॉक्टरों की टीम ने न सिर्फ एक गर्भवती महिला के पेट से 2.6 किलोग्राम के स्वस्थ बच्चे को सुरक्षित जन्म दिलाया, बल्कि ठीक उसके पीछे छिपे 10.2 किलोग्राम वजन के एक विशालकाय और जानलेवा ओवरी ट्यूमर (अंडाशय की गांठ) को भी सफलतापूर्वक काटकर बाहर निकाल दिया। यह ऑपरेशन किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि महिला के गर्भ में मासूम शिशु के साथ-साथ एक ऐसा भारी-भरकम ट्यूमर पल रहा था जो बच्चे के वजन से करीब चार गुना ज्यादा भारी था। जरा सी भी चूक जच्चा और बच्चा दोनों की जान ले सकती थी।

लेडी सर्जन्स का बेजोड़ टीमवर्क

जीएमसी की डीन डॉ. कविता सिंह और विभागाध्यक्ष डॉ. रेखा वाधवानी के कुशल नेतृत्व में इस बेहद पेचीदा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सीनियर सर्जन डॉ. पल्लवी सिंह और डॉ. अदिति खरे की टीम ने अपनी जादुई उंगलियों और सूझबूझ से मौत के मुंह से दो जिंदगियों को सुरक्षित बाहर खींच निकाला। सर्जरी के सबसे नाजुक मोड़ पर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉ. तृप्ति वत्सल्य, डॉ. जितेन्द्र कुमार और डॉ. देवांशु सराफ ने महिला की स्थिति को स्थिर बनाए रखा, जबकि जूनियर डॉक्टरों ने भी मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी निभाई।

पूरे मध्य प्रदेश में गूंज

हमीदिया अस्पताल की इस ऐतिहासिक कामयाबी की गूंज अब पूरे प्रदेश के चिकित्सा जगत में है। ट्यूमर इतना बड़ा था कि उसने पेट के भीतर बच्चे के लिए जगह ही नहीं छोड़ी थी और अंदरूनी अंगों पर भारी दबाव बना रहा था। डॉक्टरों के इस बेजोड़ तालमेल और वर्ल्ड क्लास हुनर के चलते आज मां और नवजात शिशु दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने साबित कर दिया है कि विपरीत हालातों और सीमित संसाधनों के बीच भी उनका जज्बा गंभीर से गंभीर मरीजों के लिए साक्षात वरदान है।

190 तहसीलदार और एसएलआर बने डिप्टी कलेक्टर

सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए पदोन्नति आदेश

डीपीसी की बैठक के बाद सरकार ने लिया निर्णय

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन ने लंबे समय से प्रतीक्षित पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करते हुए 190 तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख (एसएलआर) और प्रभारी डिप्टी कलेक्टरों को राज्य प्रशासनिक सेवा में डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नत कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के साथ ही ये अधिकारी अब राजस्व विभाग के बजाय सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी माने जाएंगे। जारी आदेश के

अनुसार संबंधित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में पदोन्नत किया गया है। उनकी पदस्थापना फिलहाल उसी जिले में रखी गई है, जहां वे वर्तमान में कार्यरत हैं। आदेश में उन अधिकारियों को भी पदोन्नति का लाभ दिया गया है, जिन्होंने पूर्व में प्रभारी डिप्टी कलेक्टर अथवा एसएलआर के रूप में कार्य करना स्वीकार किया था, लेकिन कार्यवाहक उच्च पद का प्रभार नहीं लिया था।

सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी पदोन्नतियां

सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी पदोन्नतियां प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। जानकारी के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव एम. सेलवेंद्रन और राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ई. रमेश कुमार ने सोमवार को इंदौर स्थित लोक सेवा आयोग कार्यालय में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में भाग लिया था। बैठक में पदोन्नति के लिए प्रस्तावित अधिकारियों के नामों पर अंतिम मुहर लगाई गई, जिसके बाद मंगलवार को पदोन्नति आदेश जारी कर दिए गए। सूत्रों के अनुसार लगभग 250 प्रभारी तहसीलदार, तहसीलदार और एसएलआर के नामों पर विचार किया गया था, जिनमें से पहले चरण में 190 अधिकारियों को डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नत किया गया है।

नायब तहसीलदारों की पदोन्नति सूची भी जल्द

राजस्व विभाग अब नायब तहसीलदारों की पदोन्नति प्रक्रिया भी पूरी करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि करीब 200 प्रभारी तहसीलदार, जो वर्तमान में नायब तहसीलदार के पद से कार्य कर रहे हैं, उन्हें नियमित तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किए जाने के आदेश एक-दो दिन में जारी किए जा सकते हैं।

5वीं व 8वीं की पुनः परीक्षा के परिणाम घोषित

5वीं में 80 फीसदी और 8वीं में 74 फीसदी से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग ने मंगलवार को कक्षा 5वीं व 8वीं की पुनः परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। विद्यार्थी व अभिभावक राज्य शिक्षा केन्द्र के परीक्षा पोर्टल पर परिणाम देख सकते हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 की पुनः परीक्षा में कक्षा 5वीं में 80.42 एवं कक्षा 8वीं में 74.16 त्न परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं, मुख्य वार्षिक परीक्षा और पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को मिलाकर इस सत्र में कक्षा 5वीं का कुल परीक्षा परिणाम 98.89 एवं कक्षा 8वीं का कुल परीक्षा परिणाम 98.19 प्रतिशत रहा है। राज्य शिक्षा केन्द्र के अपर संचालक डॉ. अरूण सिंह ने बताया कि विद्यार्थी, अभिभावक एवं शिक्षकगण उक्त परिणामों को राज्य शिक्षा केन्द्र के पर अपना रोल नम्बर डालकर देख सकते हैं। साथ ही शिक्षक, संस्था प्रमुख भी अपनी शाला का विद्यार्थीवार परिणाम इसी पोर्टल पर देख सकते हैं। गौरतलब है कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 16 से 23 जून के बीच कक्षा 5वीं व 8वीं की पुनः परीक्षाओं का आयोजन किया गया था।

भोपाल में इलेक्ट्रीशियन ने फांसी लगाकर किया सुसाइड

दो भाइयों के साथ आनंदनगर में रहता था, परिवार को भी नहीं पता कारण

भोपाल। भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र के आनंद नगर इलाके में 26 साल के इलेक्ट्रीशियन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना सोमवार शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच की है। मृतक का नाम सोनू सोनी है। सबसे पहले बड़े भाई उत्तम सोनी ने उसे फंदे पर लटका देखा था। परिजनों के अनुसार आत्महत्या के कारणों की फिलहाल जानकारी नहीं है। परिजनों के मुताबिक युवक को पहले पटेल नगर स्थित गायत्री हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उसे हमीदिया अस्पताल लाया गया।

बचपन में ही हो गया था माता-पिता का निधन

उसने 9वीं तक पढ़ाई की थी। बचपन में ही उसके माता-पिता का निधन हो गया था। वह अपने दोनों भाइयों के साथ आनंद नगर में रहता था। परिजनों का कहना है कि उन्हें आत्महत्या की वजह के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं मामले में पिपलानी थाने के प्रभारी का कहना है कि मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्ट्म के लिए भेजा है। परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

राज्य सरकार ने फिर लिया 3600 करोड़ रुपए का कर्ज

18 साल और 30 वर्ष में चुकाएंगे लोन, 5 लाख 6114 करोड़ पहुंचा राज्य सरकार पर कर्ज

भोपाल। मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने मंगलवार को बाजार से 3,600 करोड़ रुपए का नया कर्ज उठाया है। यह राशि दो अलग-अलग किश्तों में 18 वर्ष और 30 वर्ष की अवधि के लिए जुटाई गई है। इस नई उधारी के बाद चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार द्वारा लिया गया कुल कर्ज 17,400 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि प्रदेश पर कुल देनदारी बढ़कर करीब 5.6114 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह राशि बॉन्ड जारी कर और सरकारी प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) की नीलामी के माध्यम से जुटाई जाएगी। ऋण की राशि का उपयोग राज्य में उत्पादक विकास कार्यक्रमों और विभिन्न सार्वजनिक विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण में किया जाएगा। इस उधारी के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई है।

विकास कार्यों पर खर्च होगा ऋण

राज्य सरकार का कहना है कि इस ऋण का उपयोग सिंचाई, कृषि, ऊर्जा, सड़क, संचार, पेयजल, सहकारी संस्थाओं के विकास और अन्य आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। सरकार ने यह भी दावा किया है कि राज्य की परिसंपत्तियों का मूल्य उसकी कुल देनदारियों से अधिक है, जिससे वित्तीय स्थिति संतुलित बनी हुई है।

18 और 30 वर्ष की अवधि के लिए लिया गया ऋण

अधिसूचना के मुताबिक, पहली किश्त 1,600 करोड़ रुपए की है, जिसे 18 वर्ष की अवधि के लिए लिया गया है। इस पर ब्याज का भुगतान निर्धारित अवधि तक प्रत्येक वर्ष किया जाएगा। दूसरी किश्त 2,000 करोड़ रुपए की है, जिसकी परिपक्वता अवधि वर्ष 2056 तक रहेगी। दोनों ऋणों पर राज्य सरकार 7.90 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर का भुगतान करेगी। ब्याज का भुगतान प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल और 15 अक्टूबर को किया जाएगा, जबकि ऋण राशि का भुगतान बुधवार को होगा।

ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के जरिए हुई नीलामी

राजपत्र के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी आयोजित की गई, जिसमें पात्र और संस्थागत निवेशकों ने भाग लिया। गैर-प्रतिस्पर्धी निवेशकों के लिए भी निर्धारित सीमा तक निवेश की सुविधा उपलब्ध कराई गई। सरकार के अनुसार, 31 मार्च 2026 की स्थिति में मध्यप्रदेश पर कुल 4,88,714.17 करोड़ रुपए का ऋण था। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा 3,33,278.21 करोड़ रुपए के मार्केट लोन का है। इसके अलावा वित्तीय संस्थानों, केंद्र सरकार, राष्ट्रीय लघु बचत निधि और अन्य स्रोतों से लिए गए ऋण भी कुल देनदारियों में शामिल हैं।

महिलाओं की बात सुन सिर पकड़कर बैठ गए डिप्टी कलेक्टर

विधवा महिलाओं की लिस्ट थमाई, बोली- जहरीली शराब से पति और बच्चे मर गए

निवाड़ी। निवाड़ी जनसुनवाई के दौरान महिलाओं की बात सुन डिप्टी कलेक्टर सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। महिलाओं ने उन्हें शिकायती आवेदन के साथ उन महिलाओं की लिस्ट थमा दी, जिनके पति और बेटों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। यह शिकायत निवाड़ी जिले की चुरारा ग्राम पंचायत से आई है। गांव की लगभग दो दर्जन महिलाएं डिप्टी कलेक्टर अनिल तलैया के सामने जनसुनवाई में पहुंचीं और प्रशासन से गांव में शराब की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। महिलाओं का आरोप है कि गांव और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से अवैध शराब खुलेआम बेची जा रही है। महिलाओं ने बताया कि इस शराब के सेवन से कई लोगों की मौत हो चुकी है और अनेक परिवार बिखर गए हैं। उनका दावा है कि उनके पति शराब की लत और कथित जहरीली शराब के कारण असमय काल का शिकार हुए। इसके चलते कई महिलाएं विधवा हो गईं और उनके बच्चों के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

विधवा हुई महिलाओं की लिस्ट दी

जनसुनवाई में पहुंची महिलाओं ने जहरीली शराब की बिक्री रोकने के साथ-साथ लगभग डेढ़ दर्जन विधवा महिलाओं की सूची भी प्रस्तुत की। शिकायत में शांति, जयंती, ललती, रामपत सुखवाती, पार्वती, गोमा, लाडकुंवर लक्ष्मी, कुसमा, मालती, रामदेवी, गोरा, सली, सोमवती, रचना, करिश्मा और सुरेश सहित कई महिलाओं के नाम शामिल हैं, जिनके पति जहरीली शराब के कारण असमय मृत्यु को प्राप्त हुए। इन महिलाओं ने कलेक्टर जमुना भिड़े से अपने परिवारों के भरण-पोषण के लिए कोई काम या रोजगार उपलब्ध कराने की भी मांग की है, ताकि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके।

400 कमाने वाले 300 की पी रहे जहरीली शराब

विधवा जयंती आदिवासी का कहना है कि पति शराब के कारण खत्म हो गए। दो लड़के और दो लड़कियां हैं सास विकलांग हैं। दोनों लड़के भी शराब पीने लगे हैं। गौमा आदिवासी ने बताया कि उसके पति शराब के कारण खत्म हो गए। बेटा भी शराब के कारण खत्म हो गया है। अब दो नाती है जिनका पालन करने वाला भी कोई नहीं है। घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है और उन्हें भी काम नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि घर का भरण पोषण कैसे हो यह समस्या उनके सामने गंभीर है। महिलाओं का कहना है कि यूरिया खाद एवं केमिकल से जहरीली शराब बनाते हैं और दिनभर खुले आम शराब बेचते हैं जिसके कारण एक बार पीने वाले लोग दिन में चार बार शराब पीने लगे हैं। दिन भर में 400 कमाते हैं और 300 की शराब पी लेते हैं, जिसके कारण गांव में असमय मौते हो रही है और परिवार के परिवार उजड़ते जा रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करता है।

संपादकीय

ट्रंप : खेल में भी दादागिरी

अमेरिका राष्ट्रपति लगता है जीवन के हर क्षेत्र में दादागिरी और गुंडई का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। ट्रंप मानते है कि वो अमेरिका तो क्या दुनिया के हर नियम कानून से ऊपर हैं। उनकी हर बात को, आदेश को, मूर्खता को दुनिया को मानना ही पड़ेगा और दुर्भाग्य से काफी हद तक ऐसा हो भी रहा है। सारे विश्व में अपने बड़बोलेपन, मनमौजीपन और बेसिरपैर की बातों से (कु) ख्याति अर्जित कर चुके ट्रंप ने अब विश्व कप फुटबॉल में भी सीधे दखल देकर अमेरिकी फुटबॉल टीम के एक खिलाड़ी का निलंबन रद्द कराया। हैरानी की बात यह है कि फीफा अध्यक्ष ने ट्रंप के 'आदेश' को चुपचाप मान भी लिया। गौरतलब है कि इस बार फीफा कप 2026 अमेरिका के साथ-साथ मैक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप से आयोजित हो रहा है। शायद ट्रंप ने इसी का फायदा उठाया है। यही नहीं, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार भी किया है, मानो बहुत बड़ा तीर मारा हो। फीफा कप में पिछले दौर में बोस्निया-हर्जेगोविना के डिफेंडर तारिक मुहारेमोविक पर फाउल करने के लिए सीधे लाल कार्ड दिखाए जाने के बाद बेल्जियम के ख़िलाफ़ अपनी टीम के अंतिम 16 मुकाबले से बाहर होने वाले थे। लेकिन फीफा ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए इस एक मैच के प्रतिबंध को 12 महीने के लिए निलंबित कर दिया। इसकी यूईएफ़ए, बेल्जियम और इंग्लैंड के फ़ुटबॉल संघों ने आलोचना की। फ़ीफ़ा के इस फ़ैसले से अमेरिकी फॉरवर्ड स्ट्राइकर बालोगुन को बेल्जियम के ख़िलाफ़ सिएटल में खेले जा रहे मैच में उतरने की छूट मिल गई। बालोगुन ने अब तक इस टूर्नामेंट में तीन गोल किए हैं। रॉयल बेल्जियन फ़ुटबॉल एसोसिएशन (आरबीएफ़ए) ने इस कदम पर हैरानी जताई है। उसने यूनाइटेड स्टेट्स सॉकर फेडरेशन को बताया है कि फ़ैसले के ख़िलाफ़ उसकी अपील ख़ारिज होने के बाद वह बालोगुन के मैच में खेलने पर सवाल उठाता है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि फ़ीफ़ा ने 'सही निर्णय लिया।' उन्होंने कहा कि अगर प्रतिबंध लागू किया जाता, तो टूर्नामेंट पर 'एक बड़ा धब्बा' लग जाता। सोमवार को व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने फ़ीफ़ा से फ़ैसले की समीक्षा करने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें 'नहीं लगता था कि यह फ़ाउल था। ट्रंप ने पुष्टि की कि उन्होंने फ़ीफ़ा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो से बात की थी। लेकिन उन्होंने 'केवल' समीक्षा करने के लिए कहा था। ट्रंप के अनुसारमुझे लगता है कि निलंबन से एक बड़ा दाग लग जाता। मेरा मानना है कि यह फ़ैसला कमीशन ने लिया था। और यह सही फ़ैसला था।' हालांकि, यूरोपीय फ़ुटबॉल की गवर्निंग बॉडी यूईएफ़ए ने कहा कि इससे फ़ुटबॉल की अखंडता ख़तरे में पड़ गई है। अमेरिका के स्टार फ़ॉरवर्ड फोलारिन बालोगुन को दिखाए गए रेड कार्ड को प्रभावी रूप से रद्द करने के फ़ैसले ने कई सवालों को जन्म दिया है। गौरतलब है कि वर्ल्ड कप फुटबॉल के इतिहास में अब तक 189 रेडकार्ड दिखाए गए हैं, और केवल दो खिलाड़ियों ने निलंबन की सज़ा नहीं भुगती है। व्हाइट हाउस और फीफा के बीच नज़दीकी संबंधों को देखते हुए, मौजूदा वर्ल्ड कप के को-होस्ट के पक्ष में लिए गए इस अत्यंत असामान्य निर्णय पर सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि क्या इस क़दम के बाद फ़ुटबॉल के इतिहास में एक नई मिसाल कायम हो गई है? इसमें केवल 'फ़ीफ़ा अनुशासनात्मक संहिता के अनुच्छेद 27' का हवाला दिया गया। अनुच्छेद 27 फ़ीफ़ा को 'सज़ा को पूर्ण या आंशिक रूप से निलंबित करने' की अनुमति देता है। क्या कोई राजनेता इस खेल आयोजन में इस हद तक दखल दे सकता है कि जिससे नियमों की व्याख्या और अमल ही बदल जाए?

नजरिया

चित्रा माली
एसोसिएट प्रोफेसर, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विवि क्षेत्रीय केंद्र,कोलकाता

मानव अधिकारों के आईने में 'सतलुज'

टाडा और पोटा एक्ट से मेरा परिचय 2001 में (आईआईएचआर) से मानवाधिकार में पीजी डिप्लोमा करने के दौरान हुआ था। तब इस कानून के दुरुपयोग और भयावहता को जाना था और जाना था कि कैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव-अधिकारों का सरेआम हनन या कहें उल्लंघन किया जाता है। जबकि व्यक्ति के न चाहने पर भी उसको उसके मानवाधिकारों से भी वंचित नहीं किया जा सकता है। टाडा (TADA-The Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act) जिसे हिंदी में 'आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम' कहा जाता है। यह भारत का पहला व्यापक आतंकवाद विरोधी कानून था,जिसे1985 में लागू किया गया और 1987 में संशोधित कर इसे और अधिक कठोर बनाया गया था। इस अधिनियम में पुलिस को विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे। जिस के तहत पुलिस किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना आरोप-पत्र (चार्जशीट) के 180 दिनों (6 महीने) तक हिरासत में रख सकती थी और जिसे बढ़ाकर एक वर्ष तक किया जा सकता था। इस विशेषाधिकार का पंजाब पुलिस के द्वारा जमकर दुरुपयोग किया गया साथ ही इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत द्वेष,खुन्नस और प्रमोशन के लिए भी किया गया था। जसवंत सिंह खालरा एक मानवाधिकार कार्यकर्ता थे।

इन्होंने पुलिस पर फर्जी गोलीबारी में निहत्थे संदिग्धों को मारने और पंजाब में 25,000 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग न करने वाले लगभग 2,000 पुलिस कर्मी व अधिकारियों की पुलिस द्वारा हत्या का आरोप लगाया गया था। खालरा जब अपने कुछ लापता दोस्तों की तलाश कर रहे थे तब उन्हें अमृतसर नगर निगम की फाइलें मिलीं जिनमें उन लोगों के नाम,उम्र और पते दर्ज थे जिन्हें पुलिस ने मार डाला था और बाद में जला दिया था। पंजाब के 3 अन्य जिलों में भी ऐसे मामले सामने आए थे। जसवंत सिंह खालरा ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया और वे हजारों दबी जुबानों की आवाज बने। 6 सितंबर 1995 में जब खालरा अपने घर के सामने अपनी कार धो रहे थे, तब पंजाब पुलिस के कर्मियों ने उनका अपहरण कर लिया और उन्हें झबल पुलिस स्टेशन ले गए। गवाहों ने पुलिस को दोषी ठहराते हुए बयान दिए और पंजाब पुलिस के महानिदेशक कंवर पाल सिंह गिल को साजिशकर्ता बताया, जबकि पुलिस ने खालरा को गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने से इनकार किया था। इसके अतिरिक्त पुलिस ने दावा किया कि उन्हें खालरा

के ठिकाने की कोई जानकारी नहीं है। दो माह तक जब पुलिस जसवंत सिंह खालरा की तलाश नहीं कर पायी तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते जांच 1996 में,सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) को सौंप दी गई थी। सीबीआई को इस बात के सबूत मिले थे कि खालरा को तरन तारन के एक पुलिस स्टेशन में रखा गया था। सीबीआई ने हत्या और अपहरण के लिए नौ पंजाब पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की सिफारिश की थी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह संधू की 1997 में हत्या कर दी गई थी और हत्या को आत्महत्या का रूप दिया गया था। 18 नवंबर 2005 को, छह पंजाब पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया गया। दो आरोपियों,उप-पुलिस अधीक्षक जसपाल सिंह और अमरजीत सिंह को खालरा के अपहरण और हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा और अन्य को सात साल कैद की सजा सुनाई गई। 16 अक्टूबर 2007 को,न्यायमूर्ति मेहताब सिंह गिल और ए.एन. जिंदल की अध्यक्षता में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अन्य चार आरोपियों: सतनाम सिंह, सुरिंदर पाल सिंह, जसबीर सिंह (सभी पूर्व सब इंस्पेक्टर) और पृथ्वीपाल सिंह (पूर्व हेड कांस्टेबल) की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। 11 अप्रैल 2011 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चार आरोपियों द्वारा आजीवन कारावास की सजा के विरुद्ध दायर अपील को खारिज कर दिया और अशांति के दौरान पंजाब पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों की कड़ी आलोचना की। मानवाधिकारों के व्यापक दुरुपयोग के कारण टाडा एक्ट को 23 मई 1995 को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2002 में आतंकवाद से निपटने के लिए सख्त कानून पोटा बनाया गया। पोटा (POTA - Prevention of Terrorism Act) जिसका हिंदी नाम आतंकवाद निवारण अधिनियम है। भारतीय संसद पर हुए हमले के बाद आतंकवाद विरोधी अभियानों को मजबूत करने के लिए इसे लागू किया गया था।

मानवाधिकार संगठनों द्वारा इस कानून के अत्यधिक दुरुपयोग और राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाए जाने के आरोपों के कारण, इसे 2004 में यूपीए (UPA) सरकार द्वारा अध्यादेश के माध्यम से रद्द (repeal) कर दिया गया था। जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित एक हिंदी फिल्म 'सतलुज' फरवरी 2025 में रिलीज होने वाली थी। जिसका पहले नाम 'घालूघारा' (जिसका अर्थ 'नरसंहार') और 'पंजाब '95' रखा गया था,लेकिन सेंसर बोर्ड ने फिल्म और निर्माण इकाई पर आपत्ति जताते हुए 127 कट लगाने और एक नया शीर्षक देने की मांग की थी। इसके बाद फिल्म की रिलीज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई,और अंततः 3 जुलाई 2026 को बिना किसी कट के ZEE5 पर रिलीज हुई। इस फिल्म में मुख्य किरदार दिलजीत दोसांझ है जिन्होंने जसवंत सिंह खालरा की निभाई है। फिल्म को रविवार 5 जुलाई 2026 को ZEE5 से हटा दिया गया। फिल्म को हटा दिए जाने के बाद से लोगों ने जसवंत सिंह खारला को गूगल पर सर्च किया और उनके बारे में जानकारी हासिल की। यह फिल्म सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर चर्चा में है। जो व्यक्ति इस फिल्म को देख पाए वे लगातार संवेदना प्रकट कर रहे हैं,दुखी हो रहे हैं और जो नहीं देख पाए वे खेद प्रकट कर रहे हैं। इस फिल्म का निर्माण अपने आप मे एक साहसपूर्ण कार्य था जिसे हनी त्रेहान ने बखूबी निभाया है। इस फिल्म का कालखंड 1985 से 1995 का है। जो उस दौर से उस दौर की ज्यादतियों से हमें रूबरू करवाती है।

आतंकवाद विरोधी कानून कैसे मानव विरोधी साबित होता है यह भी बताती है। कानून व्यक्ति के लिए है व्यक्ति कानून के लिए नहीं है। आज भी कमोबेश हर प्रदेश में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और आरटीआई कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाता है उनकी हत्या तक कर दी जाती है। हम खबरों में पढ़ या सुन लेते हैं लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उनके लिए उनके अधिकारों और उनके परिवारों के लिए संवेदनशील है? या फिल्म बनने का इंतजार कर रहे हैं।

राजनीति

एल.एस. हरदेनिया
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

दलबदल पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए

मध्यप्रदेश में 1967 के चुनाव में काफी कठिनाई से कांग्रेस की सरकार बनी। पंडित डी.पी. मिश्र मुख्यमंत्री बने। परन्तु उनकी सरकार दलबदल से अपदस्थ कर दी गई और ज्यादा दिन नहीं टिकी। संविद सरकार के टूटने के बाद पुनः कांग्रेस सरकार गठित हुई। उसके मुखिया बने श्यामाचरण शुक्ल, जो पूर्व मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल के पुत्र थे। यह सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चल सकी। 1969 के बाद फिर चुनाव हुए कांग्रेस सरकार बनी। दलबदल करने वालों को 'आया राम गया राम' का नाम दिया गया। कांग्रेस के जो लोग कांग्रेस छोड़ कर गए थे, फिर कांग्रेस में आ गए और उन्होंने श्यामाचरण शुक्ल का नेतृत्व स्वीकार किया। जब उनसे पूछा गया कि आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी और फिर वापस क्यों आए, तो उन्होंने कहा, 'जैसे उड़ि जहाज को पंछी, पुनि जहाज पर आवै'।

पूरे देश में दलबदल पर बहस जारी है। कुछ लोग दलबदल को लाभप्रद मानते हैं तो कुछ लोगों की राय है कि इससे प्रजातंत्र की जड़ें कमजोर होती हैं। दुनिया के अनेक देशों की तरह हमारे देश में भी संसदीय प्रजातंत्र है। संसदीय प्रजातंत्र में एक निश्चित अंतराल से चुनाव होते हैं। भारत सहित दुनिया के कुछ देशों में राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर निर्वाचित प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है।

सन् 1950 में संविधान लागू होने के बाद पूरे देश में संसदीय संस्थाओं का चुनाव हुआ था और तब से लेकर लगभग 1967 तक संसदीय संस्थाएं सही अर्थों में प्रजातांत्रिक रहीं। 1967 के चुनाव में अनेक राज्यों में कांग्रेस सरकारें बनीं। परंतु जो कांग्रेसी सरकारें बनीं थीं उनमें से दलबदल हुआ। यह देश में पहला दलबदल था। उस समय कांग्रेस से इतर अन्य पार्टियों की राज्य सरकारें बनीं। उसके लिए कांग्रेस से दलबदल करवाया गया। 1967 के दलबदल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जनसंघ ने अदा की। उत्तरप्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में कुछ राजनैतिक पार्टियों ने दलबदल कर एक दूसरे की सहायता की और अनेक राज्यों में दलबदल से सरकारें बनीं जिन्हें संयुक्त विधायक दल अर्थात एसवीडी कहा गया। परंतु दलबदल से बनी हुई सरकारें ज्यादा समय नहीं चल सकीं।

मध्यप्रदेश में 1967 के चुनाव में काफी कठिनाई से कांग्रेस की सरकार बनी। पंडित डी.पी. मिश्र मुख्यमंत्री बने। परन्तु उनकी सरकार दलबदल से अपदस्थ कर दी गई और ज्यादा दिन नहीं टिकी। संविद सरकार के टूटने के बाद पुनः कांग्रेस सरकार गठित हुई। उसके मुखिया बने श्यामाचरण शुक्ल, जो पूर्व मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल के पुत्र थे। यह सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चल सकी। 1969 के बाद फिर चुनाव हुए कांग्रेस सरकार बनी।

दलबदल करने वालों को 'आया राम गया राम' का नाम दिया गया। कांग्रेस के जो लोग कांग्रेस छोड़ कर गए थे, फिर कांग्रेस में आ गए और उन्होंने श्यामाचरण शुक्ल का नेतृत्व स्वीकार किया। जब उनसे पूछा गया कि आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी और फिर वापस क्यों आए, तो उन्होंने कहा, 'जैसे उड़ि जहाज को पंछी, पुनि जहाज पर आवै'।

1967 के बाद एक और डेवलपमेंट हुआ। अनेक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियाँ बन गईं। इनमें उत्तरप्रदेश में मुलायम सिंह यादव द्वारा गठित जनता पार्टी शामिल थी। बिहार में भी नया दल बना जिसमें प्रमुख भूमिका निभाई लालू प्रसाद यादव ने। बंगाल में कुछ समय के बाद कम्युनिस्ट सरकार बनी, जिसके नेता बने ज्योति बसु। केन्द्र में भी एक समय ऐसा आया जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गैर-कांग्रेसी सरकार बनी।

दिल्ली में एच.डी. देवगौड़ा, इन्द्रकुमार गुजराल के नेतृत्व में भी केन्द्रीय सरकार बनी। लगभग सभी पार्टियां दलबदल से प्रभावित हुईं। इससे हमारे देश में प्रजातंत्र की जड़ें कमजोर होती गईं। 1985 के आसपास राजीव गांधी के नेतृत्व में दलबदल रोकने के लिए एक कानून बना जिसके अन्तर्गत सामूहिक दलबदल को वैध माना गया।

इस तरह के दलबदल अनेक राज्यों में होते रहे। मुख्यमंत्री बदलते गए, नेता बदलते गए। दलबदल राजनीति का हिस्सा बनता गया और लोकतंत्र कमजोर होता गया। विकास की दरें भी कमजोर हुईं, क्योंकि एक पार्टी अपने मेनिफेस्टो के आधार पर कुछ नीति बनाती थी और थोड़े समय के बाद उसकी सरकार हट जाती थी और फिर दूसरी पार्टी की नई सरकार दूसरी किस्म की नीति लाती थी।

दलबदल होने का एक कारण यह भी था कि हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सत्ताधारी पार्टी के किसी भी सदस्य को पार्टी की नीति का विरोध करने का अधिकार

नहीं है। यदि कोई विरोध करता है तो उसे पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है। विधेयक या नीतियों से संबंधित किसी तरह का प्रस्ताव संसद या विधानसभा में प्रस्तुत करने का अधिकार भी नहीं है।

इससे कभी-कभी विधायकों के कुछ समूहों को घुटन-सी महसूस होती थी। जब वो राज्य हित में या देश के हित में किसी नीति की आलोचना करता था, या मुख्यमंत्री या किसी अन्य मंत्री के काम का विरोध करता था, तो इसको बगावत समझा जाता था। यदि कोई विधायक अपनी व्यक्तिगत हैसियत से, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर अपना विचार प्रकट करता है तो उसे अनुशासनहीनता समझा जाता है।

इस बीच केन्द्र में इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा और वहां संयुक्त सरकार बनी। परन्तु 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी भारी बहुमत से जीतीं। जिन लोगों ने इंदिरा गांधी का विरोध किया और उन्हें मजबूर किया कि वे आपातकाल लगाएं, उनकी नीतियाँ या उनके नारे इतने मजबूत नहीं थे। 1980 में सत्ता में आने के बाद इंदिरा जी ने कहा कि यदि मुझे यह मालूम होता कि आपातकाल का विरोध करने वाले इतने कायर हैं तो मैं कभी आपातकाल नहीं लगाती।

कुल मिलाकर यह सिद्ध हुआ कि व्यक्ति के रूप में तो दलबदल खराब था ही समूह के रूप में भी दलबदल सही नहीं था। मध्यप्रदेश में भी एक लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस की सरकार बनी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। परंतु कुछ समय बाद ही उनकी सरकार को गिरा दिया गया और बड़ी संख्या में कांग्रेसी सदस्य अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए।

अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी, जो बहुत ताकतवर नेत्री समझी जाती थीं, चुनाव हार गईं, और हारने के बाद बड़ी संख्या में उनके विधायकों ने उनकी पार्टी छोड़ दी। यदि इसी तरह का सिलसिला जारी रहा तो भारत के विकास में रोड़े पड़ेंगे। क्योंकि हमारे देश में व्यवस्था ऐसी है कि शासन से संबंधित कुछ विषय केंद्र के हाथ में हैं, कुछ राज्यों के हाथ में हैं और कुछ विषय ऐसे हैं जो दोनों के पास होते हैं। इसलिए देश के विकास में राज्यों का बहुत बड़ा योगदान है। यदि इसी तरह से दलबदल जारी रहा, तो राज्य विकास नहीं कर पाएंगे। अगर राज्य विकास नहीं कर पाएंगे, तो देश भी विकास नहीं कर पाएगा।

इसलिए अब आवश्यकता इस बात की है कि दलबदल को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाए। जो सांसद या विधायक जिस दल से चुनाव जीतता है अगर वह उस दल को छोड़कर दूसरे दल में जाता है, तो संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि यदि वो अपने दल को छोड़ता है, अपने दल की नीतियों, अपने दल के मेनिफेस्टो को ठुकराता है, और यदि वह दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता स्वमेव समाप्त समझी जाए और न सिर्फ उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाए बल्कि अगले 6 साल के लिए उसका चुनाव लड़ना प्रतिबंधित कर दिया जाए।

अमेरिका में हमारे देश की तरह फेडरल सिस्टम है। पर वहाँ यदि किसी सांसद को किसी कारण से अपनी पार्टी छोड़नी पड़ती है, तो वह दूसरी पार्टी जॉइन नहीं कर पाता। प्रारंभ में दलबदल राजनीतिक कारणों से किया जाता था, अब तो कुछ मामलों में लेनदेन से दलबदल होने लगे हैं। इसलिए राजनेताओं को इस मुद्दे पर सोचना पड़ेगा और आम जनता को यह दबाव बनाना पड़ेगा कि दलबदल की प्रक्रिया पूरी तरह से प्रतिबंधित हो। अगर यह नहीं हुआ तो लोकतंत्र कमजोर पड़ेगा और देश का विकास रुक जाएगा।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

आसिम अनमोल
लेखक मध्यप्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी हैं।

स्टाइलिश भिखारियों के नायाब चोंचले

भीख माँगना कोई चोरी की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन भिखारी की शक्ल में हर एक की दृष्टि में चोर नज़र आना भिखारियों की कई परतें ज़रूर खोलता है। भिखारियों की भीख़ मांगने की गलत टाइमिंग से ही पता चल जाता है कि आप जरुरतमंद भिखारी ही नहीं हैं। आप कुछ और हैं। इसी लिए आपकी टाइमिंग में गुंडे और मवाली होने की दुर्गन्ध आ रही है। भिकारी शब्द इतनी सत्यता का प्रतीत होता था। आज उसी सत्य पर बदी पूरी मुस्तैदी के साथ हमला कर रही है । आज भीख माँगना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि स्टेटस का सवाल बनता जा रहा है। भिखारियों की भीख मांगने की सभ्यता कुछ वर्ष पहले तक कुछ ठीक ठाक थी। दरवाजे पर अपने ईगो की हनक नहीं दिखाता था भिखारी। भिखारी के आने से घर का दरवाजा तक सम्मानित हो जाता था। ऐसे शालीन तरीके से भीख मांगी जाती थी। जैसे दरवाज़े पर कोई देवता अवतरित हो गया हो। आज भिखारी खुद को भिखारी मानने को ही तैयार नहीं है । लेकिन भिखारी बनकर दरवाज़े पर ऐसे आ धमका जा रहा है जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी का कोई अधिकारी आ गया हो। भीख मांगने की हेकड़ी ऐसी जैसे भीख नहीं कोई हफ्ता वसूली की जा रही हो। भीख मांगने का स्वर जो कभी लचकदार होता था। उसमें ऐसा कड़कपन जैसे दरवाज़े पर कर्ज माँगा जा रहा हो। हाल ही में मेरे दरवाज़े की एक भिकारी ने डोर वेल बजाई। मैंने श्रद्धा पूर्वक कुछ पैसे जैसे ही हाथ पर रखे, भिखारी ने अपने मुँह का ऐसे मिला जुला नृत्य किया। जैसे मैंने उसके हाथ में कोई कानून की धारा थमा दी हो। मुझे बड़ा अजीब लगा। एक तो पैसे दूँ ऊपर से बेमतलब के ईगो का भी सामना करूँ । भिखारी के मुख से अनायास निकला बाबू जी मेरी बेटी जवान हो गई है । उसकी शादी की बहुत चिंता है। अब मुझे अपने ही दरवाज़े पर खुद के खड़े होने पर शक होने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे हम दरवाज़े पर मैरिज व्यूरो खोले बैठें हों। बेटी जवान हो गई है इसका एक और भी प्रोफेशनल मतलब समझ में

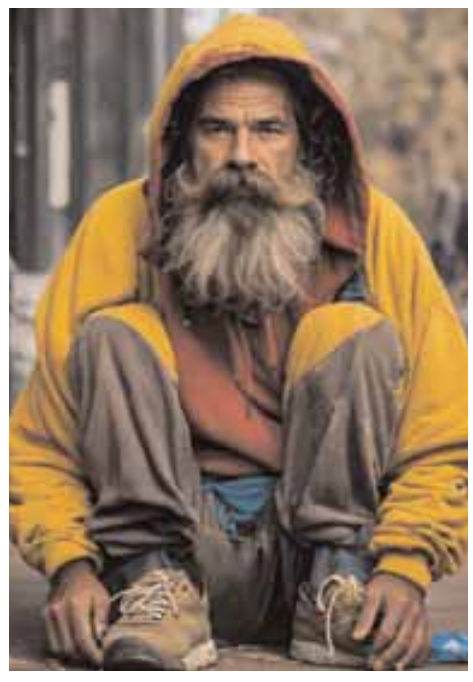

आया । उनकी जवान हो रही बेटी की विदाई का कुछ तो आर्थिक बोझ मैं भी उठाऊँ । मैंने भिखारी की आर्थिक भावनाओं को तुरंत ताड़ा। बड़े ही आदर सत्कार से भिखारी को जाने को कहा । भिखारी मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैंने उसका सत्कार नहीं उसके साथ कोई अपराध कर दिया हो। आज के भिखारी भीख़ कम मांग रहे हैं। आपके घर की कोने- कोने की जाँच ज़्यादा कर रहे हैं। पहले के भिखारी दरवाजे का अस्तित्व का ख़ास ध्यान रखते थे। क्यों कि वो सच्चे भिखारी होते थे। आज का भिखारी तो बिना अनुमति के बेखौफ घरों में घुसकर भीख मांगने की कला का सुनोयोजित प्रदर्शन कर रहा है। टोकने पर ऐसे आँखे दिखा रहा है। जैसे सरकार ने अनुमति देकर घर घर ताका झांकी करने भेजा हो। भिखारियों की यह कौन सी भीख मांगने की आँखें हैं जिनमें जरा सा भी भीख मांगने का असली जज्बा नहीं बचा। शर्म इनके डी एन ए में ही नहीं है । शर्म होती तो भी मांगने में इतने बेशर्म कैसे प्रतीत होते। भीख मांगने में इतनी जागरूकता हमने कहीं नहीं देखी। जितनी हमारे देश के भिखारियों के अंदर है।

पर्यावरण

जयदेव राठी

लेखक एडवोकेट हैं।

हीटवेव का कहर: 'बर्फीला महाद्वीप' बन रहा है 'आग की भट्टी'

यूरोप के मौसम को नियंत्रित करने वाला सबसे बड़ा कारक 'पोलर जेट स्ट्रीम' है। यह हवा की एक तेज धारा है जो आर्कटिक की ठंडी हवा को उत्तर में और भूमध्यसागर की गर्म हवा को दक्षिण में कैद करके रखती है। लेकिन आर्कटिक में तेजी से बर्फ पिघलने के कारण, ध्रुव और भूमध्यरेखा के बीच का तापमान अंतर कम हो गया है। इसके परिणामस्वरूप जेट स्ट्रीम कमजोर पड़ गई है और वह सीधी रेखा में बहने के बजाय लहराती हुई, चलती है। यह लहराहट यूरोप के ऊपर 'हाई-प्रेशर ब्लॉक' बना देती है, जिसके कारण गर्म हवा एक ही जगह पर फंस जाती है और हफ्तों तक निकल नहीं पाती है।

यूरोप यह नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने बर्फ से ढके पहाड़, एल्प्स की ठंडी वादियां, लंदन का कोहरा, और स्कैंडिनेविया की जमी देने वाली सर्दी का चित्र उभरता है। दशकों से यूरोप को 'ठंडा महाद्वीप' माना जाता रहा है, जहां गर्मियां भी सुहानी और ठंडी होती थीं। लेकिन आज का यूरोप उस कल्पना से बिल्कुल अलग है। जून 2026 के इस मौजूदा दौर में, यूरोप के कई हिस्से भयंकर हीटवेव की चपेट में हैं। स्पेन, इटली, और ग्रीस जैसे दक्षिणी देशों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है, जबकि ब्रिटेन, जर्मनी और स्कैंडिनेविया जैसे पारंपरिक रूप से ठंडे देशों में भी पारा 35-40 डिग्री के आसपास डोल रहा है। सड़कों की डामर पिघल रही है, नदियां सूख रही हैं, और जंगलों में भयंकर आग लग रही है। आखिर क्या कारण है कि जो यूरोप कभी ठंड का प्रतीक था, आज वही भयंकर गर्मी से बेहाल है।

पिछले कुछ वर्षों ने यूरोप के जलवायु इतिहास को पूरी तरह से पलट दिया है। इस साल की शुरुआत से ही यूरोप में बारिश का पैटर्न पूरी तरह बिगड़ चुका है। इटली की प्रसिद्ध नदी 'पो' और जर्मनी की रीढ़ मानी जाने वाली नदी 'राइन' का जलस्तर खतरनाक स्तर तक गिर गया है, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था और कृषि पर गहरा असर पड़ा है। फ्रांस और स्पेन में हजारों एकड़ में फैलेजंगल राख हो चुके हैं। यूरोप के बुजुर्गों के लिए यह गर्मी जानलेवा साबित हो रही है, 1300 के लगभग मौतें और अस्पताल हीटस्ट्रोक के मरीजों से भरे हुए हैं।

यूरोप का इस तरह से 'भट्टी' में तब्दील हो जाना कोई एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि यह दशकों से चल रहे पर्यावरणीय बदलावों का परिणाम है। इसके पीछे बहुत से कारण है।

यूरोप के मौसम को नियंत्रित करने वाला सबसे बड़ा कारक 'पोलर जेट स्ट्रीम' है। यह हवा की एक तेज धारा है जो आर्कटिक की ठंडी हवा को उत्तर में और भूमध्यसागर की गर्म हवा को दक्षिण में कैद करके रखती है। लेकिन आर्कटिक में तेजी से बर्फ पिघलने के कारण, ध्रुव और भूमध्यरेखा के बीच का तापमान अंतर कम हो गया है। इसके परिणामस्वरूप जेट स्ट्रीम कमजोर पड़ गई है और वह सीधी रेखा में बहने के बजाय लहराती हुई, चलती है। यह लहराहट यूरोप के ऊपर 'हाई-प्रेशर ब्लॉक' बना देती है, जिसके कारण गर्म हवा एक ही जगह पर फंस जाती है और हफ्तों तक निकल नहीं पाती है। यूरोप की गर्मी का एक बड़ा स्रोत अफ्रीका का सहारा मरुस्थल है। जलवायु परिवर्तन के कारण सहारा से उठने वाली अत्यंत गर्म और शुष्क हवाएं अब पहले से कहीं ज्यादा उत्तर की ओर बढ़ रही हैं। ये हवाएं न केवल तापमान को 40 डिग्री के पार ले जाती हैं, बल्कि अपने साथ लाल धूल भी लाती हैं, जो कभी-कभी एल्प्स के बर्फीले पहाड़ों पर जम जाती है। यह धूल बर्फ का रंग गहरा कर देती है, जिससे 'अल्बिडो इफेक्ट' कम होता है और बर्फ सूर्य की अधिक गर्मी सोखकर तेजी से पिघलती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन अनदेखा किया जाने वाला कारण है। सामान्य परिस्थितियों में, जमीन में मौजूद नमी सूर्य की गर्मी को सोखकर वाष्पित होती है, जिससे आस-पास का तापमान ठंडा रहता है। लेकिन लगातार सूखे और कम बारिश के कारण यूरोप की मिट्टी पूरी तरह सूख चुकी है। अब सूर्य की सारी ऊर्जा हवा को गर्म करने में लगती है, जिससे तापमान आसमान छूने लगता है। इसे विज्ञान की भाषा में 'पॉजिटिव फीडबैक लूप' कहते हैं।

यूरोप के शहर सैकड़ों साल पुराने हैं। इनकी सड़कें पत्थरों, कंक्रीट और ईंटों से बनी हैं, जो सूर्य की गर्मी को सोखकर दिन भर में उसे स्टोर कर लेती हैं और रात में छोड़ती हैं। यूरोप में ऐसी संस्कृति नहीं रही जहां हर घर में एयर कंडीशनर हो। जब तापमान अचानक बढ़ता है, तो ये पुरानी इमारतें 'ओवन' का काम करने लगती हैं, और रात का तापमान भी 30 डिग्री के नीचे नहीं गिरता, जिससे लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत होती है। औद्योगिक क्रांति का जन्म यूरोप में ही हुआ था। पिछले दो सौ वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका द्वारा वातावरण में छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों ने पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल सा बना दिया है। भले ही आज यूरोप अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने का दावा करे, लेकिन वातावरण में पहले से मौजूद गैसों का प्रभाव अभी भी चरम पर है। यूरोप 'विश्व का अन्न भंडार' नहीं है, लेकिन जैतून, अंगूर, 'वाइन' गेहूं और मक्का के उत्पादन में यह एक प्रमुख खिलाड़ी है। भयंकर गर्मी और सूखे के कारण फसलें खेतों में ही सूख रही हैं। इसका सीधा असर वैश्विक खाद्य कीमतों पर पड़ रहा है।

एल्प्स के ग्लेशियर, जो यूरोप की प्रमुख नदियों के स्रोत हैं, तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2050 तक यूरोप के कई प्रमुख ग्लेशियर पूरी तरह गायब हो सकते हैं। इससे न केवल जल संकट पैदा होगा, बल्कि पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। नदियों के सूखने से जलमार्ग बंद हो गए हैं, जिससे कोयला और माल ढुलाई पर भारी असर पड़ा है। साथ ही, बिजली की मांग एसी और कूलिंग सिस्टम के कारण आसमान छू रही है, जिससे यूरोप का ऊर्जा संकट और गहरा गया है। पर्यटन उद्योग, जो यूरोप की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, भी गर्मी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

यूरोप के सामने अब दो रास्ते हैं- या तो वह जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए, या फिर इस नई गर्मी के अनुकूल खुद को ढाल ले। यूरोप के शहरों को अब 'कूलिंग सिटी' के रूप में डिजाइन करने की जरूरत है। छतों पर गार्डन बनाना, सड़कों के किनारे बड़े पेड़ लगाना, और पुरानी इमारतों में इंसुलेशन का उपयोग करना अनिवार्य हो गया है। जीवाश्म ईंधन का उपयोग तुरंत बंद करके सोलर और विंड एनर्जी पर शिफ्ट होना होगा। यूरोपीय संघ का 'ग्रीन डील' अब केवल एक नीति नहीं, बल्कि अस्तित्व का सवाल बन चुका है।

पारंपरिक फसलों की जगह अब सूखा रोधी फसलों की खेती पर जोर देना होगा। पानी के संरक्षण के लिए आधुनिक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अपनाना होगा। सरकारों को हीटवेव को 'प्राकृतिक आपदा' घोषित करना होगा। बुजुर्गों और कमजोर वर्गों के लिए शहरों में 'कूलिंग सेंटर' स्थापित करने होंगे और काम करने के समय में बदलाव करने होंगे। यूरोप का यह बदला हुआ रूप केवल यूरोप की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक भयावह चेतावनी है। अगर जिस यूरोप की मिट्टी में ठंडक बसी थी, वह आज आग उगल रहा है, तो भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों का भविष्य क्या होगा? यूरोप में आ रहे इस हीटवेव का कहर हमें बताता है कि जलवायु परिवर्तन कोई दूर की कौड़िक नहीं है, बल्कि यह हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। 'ठंडे यूरोप' का मिथक अब टूट चुका है। अब समय आ गया है कि दुनिया के सभी देश अपनी पुरानी ऊर्जा नीतियों को त्यागकर पृथ्वी को बचाने की दिशा में ठोस और त्वरित कदम उठाएं। क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं रुका, तो कल को हो सकता है कि एल्प्स के बर्फबारी वाले दृश्य हमें केवल इतिहास की किताबों और म्यूजियम में ही देखने को मिलें।

वक्रोक्ति

सुदर्शन कुमार सोनी

लेखक व्यंग्यकार हैं।

सस्ता तेल और मौनव्रती तेल कंपनियाँ

जैसे ही कच्चे तेल का भाव नीचे आता है, एक अद्भुत आध्यात्मिक परिवर्तन दिखाई देता है। तेल सस्ता होते ही कंपनियाँ मौनी बाबा बन जाती हैं । न कोई विशेष चर्चा, न कोई ग्राफ, न कोई उत्साह। लगता है जैसे सस्ता कच्चा तेल किसी सरकारी गोपनीय फाइल में बंद कर दिया गया हो। उधर जनता भी कम अद्भुत नहीं है। महँगा होने पर दो दिन चर्चा करती है, तीसरे दिन उसे भाग्य मान लेती है। सस्ता होने पर भी धैर्य की मूर्ति बनी रहती है। मानो उसने नागरिक शास्त्र में पढ़ रखा हो कि 'अच्छा नागरिक वही है जो बढ़े हुए दामों को बिना शिकायत स्वीकार करे और घटे हुए दामों की प्रतीक्षा भी धैर्यपूर्वक करे।

तेल कंपनियों का स्वभाव बड़ा आध्यात्मिक है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव बढ़ता है तो उनका दुख राष्ट्रीय शोक में बदल जाता है। टीवी चैनलों पर विशेषज्ञों की फौज उतर आती है। एंकर गंभीर हो जाते हैं । ग्राफ ऊपर भागते हैं, लाल तीर चमकने लगते हैं और बताया जाता है कि पेट्रोल-डीज़ल के दाम बढ़ाना कंपनियों की मजबूरी है। उन्होंने बहुत घाटा सह लिया, अब जनता की राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाने की बारी है। ऐसे अवसरों पर मीडिया और तेल कंपनियों का तालमेल देखने लायक होता है। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर समझाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियाँ बड़ी विकट हैं। उपभोक्ता भी सिर हिलाकर मान लेता है कि वैश्विक संकट का बोझ आखिर किसी को तो उठाना ही पड़ेगा।

लेकिन जैसे ही कच्चे तेल का भाव नीचे आता है, एक अद्भुत आध्यात्मिक परिवर्तन दिखाई देता है। तेल सस्ता होते ही कंपनियाँ मौनी बाबा बन जाती हैं । न कोई विशेष चर्चा, न कोई ग्राफ, न कोई उत्साह। लगता है जैसे सस्ता कच्चा तेल किसी सरकारी गोपनीय फाइल में बंद कर दिया गया हो। उधर जनता भी कम अद्भुत नहीं है। महँगा होने पर दो दिन चर्चा करती है, तीसरे दिन उसे भाग्य मान लेती है। सस्ता होने पर भी धैर्य की मूर्ति बनी रहती है। मानो उसने नागरिक शास्त्र में पढ़ रखा हो कि 'अच्छा नागरिक वही है जो बढ़े हुए दामों को बिना शिकायत स्वीकार करे और घटे हुए दामों की प्रतीक्षा भी धैर्यपूर्वक करे।'

जब जनता का धैर्य जवाब देने लगता है, तब कहीं घोषणा होती है- 'आज पेट्रोल 50 पैसे सस्ता।' पाँच रुपये की बढ़ोतरी के तनाव का उत्तर पचास पैसे की फीकी मुस्कान से दिया जाता है। बढ़ोतरी वंदे भारत एक्सप्रेस है, राहत पैसेंजर गाड़ी। दोनों एक ही पटरी पर चलती हैं, लेकिन मंज़िल तक पहुँचने का समय अलग-अलग होता है।गंगाधर को तो लगता है कि तेल कंपनियों के दफ्तर में दो अलग-अलग घंटियाँ होंगी।

पहली बजते ही आदेश निकलता होगा- 'कच्चा तेल महँगा, प्रेस विज्ञप्ति जारी करो।' दूसरी, जो सस्ते तेल की सूचना देती होगी, शायद वर्षों से खराब पड़ी है। उपभोक्ता भी बड़े सहनशील जीव हैं। जिस सहजता से वे महँगे दामों पर टंकी फुल करवाते हैं, उसी सहजता से सस्ता होने की प्रतीक्षा भी करते रहते हैं। पेट्रोलियम मंत्री का यह तर्क भी कम रोचक नहीं कि कंपनियाँ अभी महँगे कच्चे तेल का शोधन कर रही हैं।और भी कि यह गिरावट दो चार माह तक जारी रहे तब ये कंपनियां भाव घटाने के बार में अपने भाव बनाएंगी । यानि अभी कोई गारंटी नही के उनके ये तटस्थता के मौन भाव कब तक विद्यमान रहेंगे। वो समझदार जनता को इशारा कर रहे हों जैसे। लेकिन आज तक यह नहीं सुना कि सस्ते कच्चे तेल का शोधन पूरा होते ही राहत तत्काल मिलेगी। सच यह है कि ईंधन के दाम केवल कच्चे तेल से तय नहीं होते; कर, विनिमय दर, परिवहन और कई अन्य आर्थिक कारक भी इसमें शामिल हैं। मगर आम आदमी को इतना जटिल गणित नहीं दिखता। उसका तोा अनुभव है कि महँगाई की खबर चीते की रफ्तार से दौड़ती है और राहत कछुए से भी धीमी चाल चलती है। शायद इसलिए पेट्रोल पंप पर सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज़ ईंधन नहीं, बल्कि धैर्य है। आम आदमी हर बार टंकी में पेट्रोल के साथ सस्ता होने की उम्मीद भी भरवाता है। और जब तक यह उम्मीद जिंदा रहेगी, तेल कंपनियों का मौनव्रत भी पूरी श्रद्धा से चलता रहेगा। लगता है कि तेल कंपनियों का मौत व्रत जनता के प्रदर्शन रूपी जूस पीने से ही टूटेगा।

दृष्टिकोण

डॉ. जीवन एस. रजक

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं साहित्यकार

मातृभाषा का आत्मसंताप, 'अंग्रेजी पुस्तकों' का मेला

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के डीबी मॉल में आयोजित एक पुस्तक मेले का का दृश्य मन को भीतर तक उद्वेलित कर गया! इस पुस्तक मेले में हर तरफ केवल 'अंग्रेजी पुस्तकों' की सजावट दिखाई दी। हिन्दी भाषा की पुस्तकें पूरी तरह नदारद थीं! मध्यप्रदेश एक हिन्दीभाषी राज्य है। यहाँ की मिट्टी में हिन्दी की सुगंध है, यहाँ की लोक-संस्कृति हिन्दी में गाती है, यहाँ की संवेदनाएं हिन्दी में अभिव्यक्त होती हैं और हिन्दी यहाँ की आठ करोड़ जनता के स्वर का उद्घोष है। ऐसे में अगर यहाँ हिन्दी इस तरह से अपमानित हो, तो यह निश्चित ही हमारी सांस्कृतिक चेतना के क्षीण होने का संकेत है।

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।।

– भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

अर्थात् अपनी भाषा की उन्नति ही सभी प्रकार की उन्नति का मूल है। अपनी भाषा के ज्ञान के बिना हृदय का अज्ञान और हीनता दूर नहीं हो सकती।

निश्चित रूप से अपनी मातृभाषा अपने ज्ञान, विश्वास और आत्मबोध का सबसे सशक्त साधन होती है। किन्तु जब वही मातृभाषा रोती है, तो इसके साथ संस्कृति, इतिहास और समाज की आत्मा भी विलाप करती है। पश्चिमीकरण के दुष्परिणामों के कारण बदलते परिवेश में हमारी मातृभाषा हिन्दी की व्यथा भी कुछ ऐसी ही हो गई है।

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के डीबी मॉल में आयोजित एक पुस्तक मेले का का दृश्य मन को भीतर तक उद्वेलित कर गया! इस पुस्तक मेले में हर तरफ केवल 'अंग्रेजी पुस्तकों' की सजावट दिखाई दी। हिन्दी भाषा की पुस्तकें पूरी तरह नदारद थीं! मध्यप्रदेश एक हिन्दीभाषी राज्य है। यहाँ की मिट्टी में हिन्दी की सुगंध है, यहाँ की लोक-संस्कृति हिन्दी में गाती है, यहाँ की संवेदनाएं हिन्दी में अभिव्यक्त होती हैं और हिन्दी यहाँ की आठ करोड़ जनता के स्वर का उद्घोष है। ऐसे में अगर यहाँ हिन्दी इस तरह से अपमानित हो, तो यह निश्चित ही हमारी सांस्कृतिक चेतना के क्षीण होने का संकेत है।

हम अंग्रेजी भाषा के विरोधी नहीं हैं। अंग्रेजी भाषा ज्ञान-विज्ञान, वैश्विक संवाद और आधुनिक शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भाषा है। उसका सम्मान होना चाहिए। किन्तु क्या अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करके ही आधुनिक बना जा सकता है? क्या प्रगति का अर्थ अपनी जड़ों से विमुख होना है? यदि ऐसा है, तो यह विकास नहीं, आत्मविस्मृति है। कदाचित् इसीलिए राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त कहते हैं-

'कैसे निज सोए भाग को कोई सकता है जगा,
जो निज भाषा-अनुराग का अंकुर नहीं उर में उगा।'

अर्थात् जिसके हृदय में अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम नहीं है, वह अपने राष्ट्र और अपने भाग्य का जागरण कभी नहीं कर सकता।

विडंबना यह है कि आज लोग अंग्रेजी को ज्ञान का पर्याय और हिन्दी को केवल व्यवहार की भाषा मानने लगे हैं। यह दृष्टि न तो दूरदर्शी है और न ही न्यायसंगत। अंग्रेजी सीखना व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक हो सकता है, किन्तु अपनी मातृभाषा को भूल जाना कभी भी प्रगति का प्रमाण नहीं हो सकता। जो समाज अपनी मातृभाषा से दूर हो जाता है, वह धीरे-धीरे अपनी संस्कृति और अपनी आत्मा से दूर होने लगता है।

मातृभाषा पीढ़ियों के अनुभव, लोकजीवन की सुगंध, संस्कृति की चेतना, सभ्यता की निरंतरता और

राष्ट्रीय अस्मिता की वाहक होती है। तुलसी, सूर, कबीर, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, दिनकर, अज्ञेय और असंख्य साहित्यकारों ने हिंदी को जन-जन की चेतना का स्वर बनाया है। अगर आज हिंदी के पाठक ही हिंदी से विमुख होने लगे, तो यह निश्चित ही उन महान् साहित्य मनीषियों की विरासत के प्रति अन्याय होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि भाषा का सम्मान पाठकों की प्रतिबद्धता से आता है। जब हम हिंदी की पुस्तकें खरीदेंगे, हिंदी में लिखेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, अपने बच्चों को हिंदी साहित्य से जोड़ेंगे और पुस्तक मेलों में हिंदी की समृद्ध उपस्थिति की अपेक्षा करेंगे, तभी हम आने वाली पीढ़ियों के लिए हिंदी का सम्मान बचा पाएंगे।

भोपाल भारत के बिल्कुल हृदय में स्थित अपनी एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान वाला शहर है। यहाँ 'भारत भवन' जैसे सांस्कृतिक केंद्र हैं। जनजातीय संग्रहालय, मानव संग्रहालय, राज्य संग्रहालय और रविन्द्र भवन जैसे संस्थान हैं, जो हमारी सांस्कृतिक चेतना को जाग्रत करते हैं। मध्यप्रदेश देश का एकमात्र राज्य है, जिसके पास अपनी भाषाई अकादमियाँ हैं। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंतर्गत भोपाल को 'लिटरेचर सिटी' के रूप में मान्यता दिलाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। ये सब विशेषताएँ उसी शहर की हैं, जहाँ पुस्तक मेलों से हिन्दी भाषा का साहित्य नदारद है, यह हम सब के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है।

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं- 'हिन्दी भारत की राष्ट्रीय चेतना की वाहिका है।' बड़े शर्म की बात है कि आज वैश्वीकरण और तकनीकी युग में कतिपय स्थानों और लोगों में हिन्दी बोलने में संकोच और अंग्रेजी बोलने में गौरव का भाव देखा जाता है। यह मानसिकता आत्महीनता की परिचायक है। विदेशी भाषा का ज्ञान निश्चित ही उपयोगी है, किन्तु अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करके अर्जित किया गया ज्ञान कभी भी आत्मिक संतोष नहीं दे सकता। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति में हिन्दी साहित्य एवं भारतीय भाषाओं के महत्त्व को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया है। डिजिटल माध्यमों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साहित्य, पत्रकारिता और सामाजिक संचार के विस्तृत होते संसार में हिन्दी की संभावनाएँ पहले से कहीं अधिक बढ़ी हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम हिन्दी को व्यवहार, शिक्षा, शासन-प्रशासन और ज्ञान-विज्ञान की भाषा बनाने का संकल्प लें।

भारतीय संस्कृति सदैव 'अनेकता में एकता' की पक्षधर रही है, और हमारी इस एकता को समृद्ध करने में हिन्दी का योगदान अभूतपूर्व है। इसीलिए आचार्य विनोबा भावे कहते हैं- 'हिन्दी देश को जोड़ने वाली भाषा है।' हमारी मातृभाषा हिन्दी ने हमें समृद्ध बनाया है, हमारी सांस्कृतिक चेतना को पहचान दी है। इसके बाद भी अगर हम अपने घर में ही हिन्दी को सम्मान नहीं दे सकते तो ये हमारे लिए 'अपमानबोध' और हिन्दी के लिए 'आत्मसंताप' की बात है। अपनी मातृभाषा का सम्मान भारत की आत्मा, उसकी संस्कृति, उसके इतिहास, उसके भविष्य और उसके आत्मबोध का सम्मान है। याद रहे, जब मातृभाषा मुस्कुराती है, तभी राष्ट्र की आत्मा को संतोष होता है।

अभिव्यक्ति

अदिति सिंह भदौरिया
लेखक स्तंभकार हैं।

बढ़ती शिक्षा और घटते संवाद

आज का समय उपलब्धियों का समय है। हर घर में डिग्रियों की संख्या बढ़ रही है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई वैज्ञानिक, तो कोई विदेश की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त कर रहा है। बच्चों के हाथों में किताबें हैं, युवाओं के पास आधुनिक तकनीक है, और दुनिया हमारी उँगलियों पर सिमट आई है। शिक्षा का स्तर पहले की अपेक्षा कहीं अधिक ऊँचा हुआ है। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा प्रश्न है, जो मन को बार-बार झकझोरता है,क्या हमारी शिक्षा के साथ हमारे संवाद भी उतने ही समृद्ध हुए हैं? दुर्भाग्य से इसका उत्तर 'नहीं' की ओर झुकता दिखाई देता है।

हम पढ़-लिख तो बहुत रहे हैं, लेकिन एक-दूसरे को समझना भूलते जा रहे हैं। हमारे पास शब्दों का विशाल भंडार है, पर दिल की बात कहने के लिए समय नहीं है। हम भाषाओं में निपुण हो गए हैं, लेकिन अपनों की चुप्पी की भाषा पढ़ना नहीं सीख पाए। यही हमारे समय की सबसे बड़ी विडंबना है।

कभी ऐसा समय था जब परिवार के सभी सदस्य शाम को एक साथ बैठते थे। दिनभर की बातें होती थीं, हँसी गूँजती थी, शिकायतें भी होती थीं और उनका समाधान भी निकल आता था। बच्चे अपने मन की बात बिना डर के कह देते थे। माता-पिता केवल सलाह नहीं देते थे, बल्कि सुनते भी थे। उस समय घरों की दीवारें छोटी थीं, लेकिन दिल बहुत बड़े थे।

आज घर बड़े हो गए हैं, कमरों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन बातचीत के लिए समय कम पड़ गया है। एक ही घर में रहने वाले लोग मोबाइल की स्क्रीन पर अधिक जुड़े हुए हैं, एक-दूसरे के मन से कम। कई बार पूरा परिवार साथ बैठा होता है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी अलग दुनिया में खोया रहता है। संवाद की जगह संदेशों ने ले ली है और आँखों में झाँककर बात करने की जगह इमोजी ने।

शिक्षा हमें केवल सफल बनाना नहीं सिखाती, बल्कि संवेदनशील बनाना भी सिखाती है। यदि हमारी डिग्रियाँ हमें दूसरों के आँसू पढ़ना नहीं सिखा रहीं, यदि हमारा ज्ञान हमें किसी टूटे हुए मन को संभालने की क्षमता नहीं दे रहा, तो कहीं न कहीं हमारी शिक्षा अधूरी है।

आज बच्चों के पास अच्छे विद्यालय हैं, आधुनिक पुस्तकें हैं, ऑनलाइन पाठ्यक्रम हैं और अनगिनत अवसर हैं। लेकिन क्या उनके पास ऐसा कोई व्यक्ति है, जिससे वे बिना झिझक अपने मन की हर बात कह सकें? कितने बच्चे अपनी असफलता, अपने डर, अपनी उलझनों या अपनी गलतियों को अपने माता-पिता के सामने सहजता से रख पाते हैं? और कितने माता-पिता अपने बच्चों की बात पूरी शांति से सुनने का धैर्य रखते हैं?

यही संवाद का अभाव धीरे-धीरे रिश्तों में दूरी बनाता है। अक्सर हम सामने वाले के व्यवहार का निर्णय उसके शब्दों से पहले ही कर लेते हैं। बिना पूरी बात सुने निष्कर्ष निकाल लेते हैं। किसी की चुप्पी को अहंकार समझ लेते हैं, किसी की कठोरता के पीछे छिपे दर्द को नहीं देख पाते। शायद इसलिए क्योंकि हमने सुनना छोड़ दिया है। हम उत्तर देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं।

आज मानसिक तनाव, अकेलापन और अवसाद जैसी समस्याएँ केवल चिकित्सा का विषय नहीं रह गई हैं। इनके पीछे कहीं न कहीं संवाद की कमी भी एक बड़ा कारण है। कई लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई ऐसा नहीं मिलता जो बिना टोके, बिना परखे और बिना निर्णय दिए उनकी बात सुन सके। कभी-कभी किसी व्यक्ति को सलाह की नहीं, केवल एक सच्चे श्रोता की आवश्यकता होती है।

विडंबना यह है कि आज हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बातें कर लेते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से कुछ ही सेकंड में जुड़ जाते हैं, लेकिन अपने ही घर में बैठे व्यक्ति के मन तक पहुँचने का रास्ता खो चुके हैं। तकनीक ने दूरी कम की है, पर कई बार दिलों के बीच की खामोशी और गहरी कर दी है।

वास्तविक शिक्षा वही है जो हमें विनम्र बनाए, धैर्य सिखाए और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना सिखाए। यदि कोई बच्चा सौ में सौ अंक लाता है, लेकिन किसी रोते हुए मित्र के आँसू नहीं समझ पाता, तो उसकी शिक्षा अधूरी है। यदि कोई उच्च पद पर पहुँच जाता है, लेकिन अपने माता-पिता की आँखों में छिपी प्रतीक्षा नहीं पढ़ पाता, तो उसकी सफलता भी कहीं न कहीं अधूरी है।

हमें अपने बच्चों को केवल प्रतियोगिता जीतना नहीं सिखाना चाहिए, बल्कि संवाद करना भी सिखाना चाहिए। उन्हें यह समझाना होगा कि हर रिश्ते की नींव विश्वास और बातचीत पर टिकी होती है। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद तब जन्म लेते हैं जब संवाद समाप्त हो जाता है। एक सच्ची बातचीत कई गलतफहमियों को जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर सकती है।

आइए, हम अपने घरों में फिर से संवाद की परंपरा लौटाएँ। भोजन के समय मोबाइल से अधिक एक-दूसरे को महत्व दें। अपने बच्चों से केवल यह न पूछें कि परीक्षा कैसी हुई, बल्कि यह भी पूछें कि उनका मन कैसा है। अपने माता-पिता से केवल उनकी दवाइयों की जानकारी न लें, बल्कि उनके अकेलेपन को भी सुनें। अपने मित्रों से केवल औपचारिक बातें न करें, बल्कि उनके मौन को भी समझने का प्रयास करें।

शिक्षा हमें ऊँचाइयों तक पहुँचा सकती है, लेकिन संवाद ही हमें इंसान बनाए रखता है। इसलिए आवश्यक है कि हम शैक्षणिक योग्यताओं की दौड़ में अपने शब्दों की गर्माहट, अपने संबंधों की मिठास और अपने संवाद की संवेदनशीलता को कभी खोने न दें। क्योंकि जब संवाद जीवित रहता है, तभी रिश्ते जीवित रहते हैं, और जहाँ रिश्ते जीवित रहते हैं, वहीं जीवन अपनी सबसे सुंदर अनुभूति देता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग - 719

बायपास पर डंपर ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर

भिंड। राष्ट्रीय राजमार्ग-719 बायपास पर सोमवार देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियों को पलभर में मातम में बदल दिया। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे दो बाइक सवार युवकों को तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर भेजा गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, भितरवार निवासी 25 वर्षीय विकास जाटव अपने रिश्तेदार दीपक जाटव (26) के साथ बाइक से एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने भवानीपुर जा रहे थे। रात करीब साढ़े नौ से दस बजे के बीच जैसे ही उनकी बाइक संस्कृति मैरिज गार्डन के सामने पहुंची, पीछे से तेज गति से आ रहे डंपर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि विकास जाटव ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने विकास को मृत घोषित कर दिया, जबकि दीपक की नाजुक हालत को देखते हुए उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया। हादसे के तुरंत बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश के साथ पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

1500 रुपये के कर्ज ने छात्र को ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसाया

50 फ़ीसदी ब्याज के जाल में फंसाकर एक साल तक घर से गायब कराता रहा लाखों के जेवर

ग्वालियर। शहर के मुरार थाना क्षेत्र में ब्लैकमेलिंग, अवैध वसूली और धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। महज 1500 रुपये उधार लेने के बाद 12वीं के एक छात्र को उसके ही रिश्ते के नाबालिग भाई ने कथित रूप से ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसा लिया। आरोप है कि आरोपी ने छात्र का वीडियो बनाकर उसे बदनाम करने और पुलिस कार्रवाई की धमकी दी। भय के कारण छात्र लगभग एक वर्ष तक घर और दुकान से चोरी-छिपे सोने के जेवर निकालकर आरोपी को देता रहा। मामले का खुलासा तब हुआ, जब व्यापारी पिता ने घर और दुकान के लॉकर से लाखों रुपये मूल्य के आभूषण गायब पाए।

शिकायतकर्ता कमल किशोर गुप्ता मुरार क्षेत्र के निवासी और किराना व्यवसायी हैं। उनका 17 वर्षीय पुत्र 12वीं कक्षा का छात्र है। 29 जून को वे पारिवारिक कार्य से इंदौर गए थे। 2 जुलाई को लौटने के बाद उन्होंने घर और दुकान की जांच की तो करीब 10 तोला सोने के जेवर गायब मिले। इनमें हार, चेन, चूड़ियां, झुमके सहित अन्य आभूषण शामिल थे। कुछ जेवर ग्राहकों द्वारा गिरवी रखे गए थे।

पूछताछ में बेटे ने बताई पूरी कहानी : गहनों के संबंध में पूछताछ करने पर छात्र ने पूरी घटना परिवार को बताई। उसने बताया कि कुछ समय पहले उसने अपने रिश्ते के एक नाबालिग भाई से 1500 रुपये उधार लिए थे। यह राशि आरोपी ने अपने एक परिचित के माध्यम से दिलवाई थी। इसके बाद आरोपी ने उस रकम पर 50 प्रतिशत मासिक ब्याज जोड़ना शुरू कर दिया। ब्याज और कथित पेनल्टी के नाम पर रकम लगातार बढ़ाई जाती रही और छात्र पर दबाव बनाया गया।

छात्र के मुताबिक, रुपये देते समय आरोपी ने उसका वीडियो बना लिया था। बाद में उसी वीडियो के आधार पर वह उसे लगातार धमकाता रहा। आरोपी का कहना था कि यदि पैसे नहीं दिए तो वह वीडियो सार्वजनिक कर देगा, चोरी का झूठा आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत करेगा और परिवार के सामने उसकी निजी बातें उजागर कर देगा। इन धमकियों से छात्र मानसिक रूप से भयभीत हो गया।

ब्लैकमेलिंग से परेशान छात्र ने पिछले लगभग एक वर्ष के दौरान घर की अलमारी और दुकान के लॉकर से थोड़े-थोड़े कर सोने के जेवर निकालकर आरोपी को देना शुरू कर दिया। परिवार का आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम में आरोपी का एक अन्य साथी भी शामिल था, जो फोन पर छात्र को धमकाता था। आरोपी के दबाव में छात्र ने दुकान के गल्ले की पेटी का ताला तक तुड़वाया और वहां रखे कई सोने के आभूषण भी आरोपियों को सौंप दिए। परिजनों की शिकायत पर मुरार थाना पुलिस ने नाबालिग आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, धमकी और आभूषण हड़पने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी

अशोकनगर रेलवे ट्रैक पर मिली 18 वर्षीय छात्रा की लाश

छोटे भाई के जन्मदिन की तैयारी के बीच मातम मोबाइल घर पर छोड़कर निकली थी छात्रा

अशोकनगर। शहर में एक 18 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। छात्रा का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वह घर से छोटे भाई के जन्मदिन के लिए केक और कपड़े खरीदने की बात कहकर निकली थी, लेकिन कुछ घंटों बाद परिजनों को उसकी मौत की सूचना मिली। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। मृतका की पहचान राधिका शर्मा (18) के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, वह सोमवार शाम करीब 6 बजे घर से बाजार जाने के लिए निकली थी। घर में छोटे भाई के जन्मदिन की तैयारियां चल रही थीं और सभी उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे। देर रात सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक पर एक युवती का शव मिला है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान राधिका के रूप में की। पुलिस के अनुसार, स्टेशन मास्टर ने सूचना दी थी कि एक युवती अचानक ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।

रेलवे ट्रैक तक कैसे पहुंची, यही सबसे बड़ा सवाल

परिजनों का कहना है कि राधिका के घर से बाजार तक जाने वाले रास्ते में रेलवे ट्रैक नहीं पड़ता। ऐसे में वह ट्रैक तक कैसे पहुंची, यह जांच का प्रमुख विषय बना हुआ है। पुलिस फिलहाल हादसा, आत्महत्या और अन्य संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है।

जांच के दौरान पुलिस को राधिका के मोबाइल में दो लोगों से हुई बातचीत के संकेत मिले हैं। प्रारंभिक जांच में कुछ संदेश डिलीट पाए गए हैं।

पुलिस डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना से पहले उसकी किससे बातचीत हुई थी और क्या उसका इस मामले से कोई संबंध है। परिवार के मुताबिक, राधिका ने इसी वर्ष 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और आगे कॉलेज में प्रवेश लेने की तैयारी कर रही थी। परिजनों का कहना है कि पिछले तीन-चार दिनों से वह मानसिक तनाव में दिखाई दे रही थी, हालांकि उन्होंने इसके पीछे की वजह स्पष्ट नहीं बताई। राधिका चार भाई-बहनों में दूसरे नंबर की थी। उसके पिता मूल रूप से बहादुरपुर क्षेत्र के कलुआखेड़ी गांव के निवासी हैं और पिछले करीब 20 वर्षों से अशोकनगर शहर में रह रहे हैं

'काला हिरण' फिल्म निर्माता को मिली जान से मारने की धमकी

दतिया। फिल्म 'काला हिरण' के निर्माता अमित जानी को कथित तौर पर पाकिस्तान के मोबाइल नंबरों से जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। आरोप है कि धमकी देने वाले व्यक्ति ने व्हाट्सएप के जरिए ऑडियो और वीडियो संदेश भेजकर फिल्म की रिलीज रोकने की चेतावनी दी। साथ ही कहा कि यदि फिल्म निर्धारित समय पर रिलीज हुई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

जानकारी के अनुसार, नोएडा निवासी अमित जानी दतिया स्थित मां पीतांबरा पीठ के दर्शन के लिए आए थे और शहर के एक निजी होटल में ठहरे हुए थे। इसी दौरान उनके मोबाइल पर पाकिस्तान के नंबरों से कॉल, व्हाट्सएप संदेश और कथित धमकी भरे वीडियो प्राप्त हुए। घटना के बाद उन्होंने दतिया कोतवाली पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत में बताया गया है कि पहले देर रात एक पाकिस्तानी नंबर से ऑडियो और वीडियो संदेश भेजे गए। इसके बाद अगले दिन सुबह दूसरे नंबर से कॉल कर फिल्म की रिलीज रोकने की बात कही गई। कॉल करने वाले ने कथित रूप से कहा कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के बावजूद उन्हें निशाना बनाया जाएगा और फिल्म रिलीज होने पर बम विस्फोट की धमकी दी।

अमित जानी का दावा है कि भेजे गए वीडियो में एक व्यक्ति आधुनिक हथियारों के साथ दिखाई दे रहा है। वीडियो में ग्रेनेड, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) सहित अन्य हथियार प्रदर्शित किए गए हैं। पुलिस ने इन वीडियो, कॉल रिकॉर्ड और व्हाट्सएप संदेशों को जांच के दायरे में लेते हुए प्रकरण दर्ज कर लिया है।

घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस के साथ सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि धमकी देने वाले नंबरों और डिजिटल साक्ष्यों की तकनीकी जांच कराई जा रही है तथा मामले के हर पहलू की पड़ताल की जा रही है।

अमित जानी उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले फिल्म निर्माता, लेखक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। वह 'जानी फायरफॉक्स मीडिया' प्रोडक्शन हाउस का संचालन करते हैं और वास्तविक घटनाओं पर आधारित फिल्मों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। उनकी चर्चित फिल्मों में उदयपुर फाइल्स, कराची टू नोएडा और काला हिरण शामिल हैं।

काला हिरण शिकार मामला : फिल्म काला हिरण वर्ष 1998 के चर्चित काला हिरण शिकार प्रकरण की पृष्ठभूमि पर आधारित बताई जा रही है। यह मामला उस समय सामने आया था जब अभिनेता सलमान खान फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर में थे। इस मामले में उनके साथ अन्य कलाकारों के नाम भी सामने आए थे। वर्ष 2018 में निचली अदालत ने सलमान खान को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई थी, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। फिलहाल यह मामला राजस्थान हाई कोर्ट में विचाराधीन है और अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है।

कलेक्टर के निर्देश पर नगर पंचायत परिषद परिसर में स्थानीय समस्याओं के निराकरण की बैठक आयोजित

सोहागपुर। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार नगर की स्थानीय समस्याओं के निराकरण एवं जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा करने के उद्देश्य से नगर पंचायत परिषद परिसर में परिचर्चा बैठक का आयोजन नगर परिषद अध्यक्ष लता यशवंत पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने-अपने वार्डों की विभिन्न समस्याओं एवं आवश्यकताओं को विस्तार से अवगत कराया । जिसमें पेयजल, स्वच्छता, सड़क, प्रकाश व्यवस्था, आवास सहित अन्य जनसुविधाओं से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की ।

नगर पंचायत परिषद अध्यक्ष श्रीमती लता यशवंत पटेल एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी धर्मेन्द्र शर्मा ने सभी समस्याओं को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए उनके शीघ्र एवं प्रभावी निराकरण का आश्वासन दिया। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी प्रदान किए गए। बैठक में नगर पंचायत परिषद उपाध्यक्ष आकाश रघुवंशी, अध्यक्ष प्रतिनिधि यशवंत पटेल, पार्षद धर्मदास बेलवंशी, पार्षद आशीष मालवीया, पार्षद भास्कर मांझी, एल्डरमैन नितिन कहार, एल्डरमैन राकेश मंडल, पार्षद प्रतिनिधि जगदीश अहिरवार, पार्षद प्रतिनिधि मोहन कहार, पार्षद प्रतिनिधि दीपक साहू, उपयंत्री बृजेश खानोरकर, दयाशंकर कुड़मी, सरला सनकत, संजय परसाई एवं रजनी ठाकुर उपस्थित थे।

किसान मजदूर महासंघ के धरनास्थल पहुंची अनुविभागीय अधिकारी डॉ. बबीता राठौर, किसानों ने ज्ञापन सौंपा

सोहागपुर। किसान मजदूर महासंघ के तत्वावधान में नवीन बस स्टैंड पर शत-प्रतिशत मूंग खरीदी को लेकर धरना आंदोलन किया गया। धरनास्थल पर अनुविभागीय अधिकारी डॉ. बबीता राठौर, एसडीओ पुलिस संजू चौहान,नगर निरीक्षक गिरीश त्रिपाठी पहुंचे। इस अवसर पर किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारी केसरी सिंह पटेल ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन का वाचन करके अनुविभागीय अधिकारी एवं एसडीओ पुलिस को सौंपा। इस ज्ञापन में कहा गया है कि किसानों की ज्वलंत समस्याओं के निराकरण किया जाए।

मध्यप्रदेश के समस्त ग्रीष्म कालीन मूंग उत्पादक जिलों में नर्मदापुरम सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी की मात्रा 1 क्विंटल 20 किलो प्रति एकड़ से पूरी तरह असंतुष्ट हैं। किसानों को शासकीय खरीदी कम मात्रा में होने से आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ प्रदेश के किसानों की ओर से मांग करता है। कि किसानों

की संपूर्ण उपार्जित मूंग शत प्रतिशत समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए।ई-टोकन खाद वितरण प्रणाली के तकनीकी कारणों से किसानों को डीएपी यूरिया एवं अन्य खाद रकवे के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाए। ई-टोकन खाद वितरण प्रणाली में सुधार किया जाए। अन्यथा ई-टोकन खाद वितरण व्यवस्था की बाध्यता समाप्त की जाए। धान की खेती हेतु विद्युत सप्लाई की आवश्यकता होती है। जिससे किसान की धान की रोपाई समय पर हो सके। इसलिए संपूर्ण जिले के किसानोंको पर्याप्त 10 घण्टे विद्युत प्रदाय कराई जाए। खरीफ की फसल के दौरान खेतों के कच्चे मार्ग गोहे पूरी तरह खराब हो जाते हैं। खेतों के मार्ग निर्माण कराये जाए। संपूर्ण जिले की गौशालाओं का नियमित निरीक्षण एस.डी.एम. स्तर अधिकारियों से कराकर सड़कों पर खड़े रहने वाले गौवंश को गौशालाओं में सुरक्षित किया जाए। उक्त मांगों का तत्काल प्रभाव से निराकरण किया जाए अन्यथा राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ एवं सोमनाथ किसान मजदूर आदिवासी संगठन, उग्र आन्दोलन करने को विवश होगे। जिसकी समस्त जबाबदारी शासन प्रशासन की होगी। इस अवसर केसरी सिंह पटेल, राजकुमार रघुवंशी विक्रमसिंह पटेल, सतीश रघुवंशी गोपाल पाटीदार, गीता मीणा, शिवराज राजोरिया घनश्याम पटेल, रमाकांत मीना, रामेश्वर पटेल, जिला अध्यक्ष शिवराज राजोरिया, उपाध्यक्ष जीतेंद्र भार्गव, आदि उपस्थित थे। इसके पूर्व धरना स्थल पर कई वक्ताओं ने मूंग खरीदी को लेकर सरकार की आलोचना की गई। इसी अवसर सरकार के खिलाफ नारेबाजी के साथ किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी, गौ माता की जय जयकार आदि नारेबाजी की गई।

संक्षिप्त समाचार

सिमरोदा में ग्रामीणों को साइबर ठगी से बचने की सीख

उमरावगंज। पुलिस आमजन को डिजिटल और साइबर सुरक्षा के लिए सेफ क्लीन 2.0 अभियान चला रही है। पुलिस चौराहा, बाजार, स्कूल, सार्वजनिक जगहों पर लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचाने के लिए जागरूक कर रही है। अभियान के तहत उमरावगंज थाना प्रभारी वीरेंद्र विश्वकर्मा ने थाना क्षेत्र के ग्राम सिमरोदा में ग्रामीणों को साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधी फर्जी कॉल, एसएमएस, ऑनलाइन लोन, निवेश, बैंक केवाईसी अपडेट, फर्जी नौकरी, ओटीपी, क्यूआर कोड, संदिग्ध लिंक के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। उन्होंने अपील की कि किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ बैंक या निजी जानकारी साझा न करें।

90 साल के रिटायर्ड शिक्षक ने दिया पर्यावरण संदेश

ओबेदुल्लागंज। नगर प्रशासन विभाग के अमृत हरित महोत्सव अभियान से प्रेरित होकर नगर के 90 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक लक्ष्मी चंद जैन ने पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि पौधों का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, इसलिए स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। लक्ष्मी चंद जैन ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से हर वर्ष पौधारोपण कर रहे हैं और इसे अपने जीवन का नियमित संकल्प मानते हैं। उन्होंने कहा कि पेड़-पौधे मानव जीवन का आधार हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल का संकल्प लेना चाहिए।

बिजली खंभे में करंट उतरा, गाय की तड़पकर मौत

विदिशा। बरेठ रोड पर एसडीएम बंगले के पीछे की बस्ती में रविवार सुबह बिजली के खंभे में करंट उतर गया। करंट की चपेट में आने से एक गाय की मौके पर ही तड़प-तड़पकर मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दूसरी गाय को हल्का झटका लगा। वह भाग निकली। उसकी जान बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक खंभे के आसपास बारिश का पानी भरा था। खंभे में करंट उतरने से पानी में भी करंट फैल गया। वहां से गुजर रही गाय करंट की चपेट में आ गई। स्थानीय निवासी प्रीति पाल ने बताया मृत गाय उनकी थी।काला बाग फीडर बंद मोहल्ले के लोगों ने बिजली कंपनी को बताया। कालाबाग फीडर बंद कराया। इसके बाद पहुंचे बिजली कर्मचारियों ने जांच की। तकनीकी खराबी दूर की। स्थिति सामान्य की। लोगों ने कहा घटना सुबह हुई। बड़ा हादसा टल गया। दिन में आवाजाही के समय करंट फैलता तो कोई राहगीर भी चपेट में आ सकता था। लोगों ने गाय के मालिक को उचित मुआवजा देने की मांग की।

बारिश से खेतों में लौटी रौनक, धान की नर्सरी तैयार करने में जुटे किसान

सलामतपुर। मानसून की पहली बारिश ने सलामतपुर क्षेत्र में खरीफ सीजन की तैयारियों को रफ्तार दी। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने से किसानों के चेहरे खिले और खेतों में जुताई शुरू हुई। किसान धान की नर्सरी तैयार करने में जुटे। खेतों में कृषि गतिविधियां बढ़ीं।सलामतपुर और आसपास का इलाका धान उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहां उपजाऊ मिट्टी होने से जल की उपलब्धता पर्याप्त रहती है। हर वर्ष बासमती सहित विभिन्न किस्मों के धान की अच्छी पैदावार होती है। यहां के चावल की मांग दूर-दराज की मंडियों तक रहती है। मानसून की दस्तक के साथ किसान रोपाई की तैयारी में लग गए। अधिकांश किसान धान की सीधी बुआई नहीं करते। नर्सरी पद्धति अपनाते हैं। सीमित क्षेत्र में बीज बोते हैं। पौध तैयार करते हैं। करीब 21 से 25 दिन बाद पौध तैयार होती है। मुख्य खेतों में मचाई होती है। इसके बाद रोपाई होती है। किसानों के अनुसार इस पद्धति से पौध का विकास बेहतर होता है जिससे उत्पादन अधिक मिलता है।किसानों को इस बार अच्छी मानसूनी बारिश की उम्मीद है।

अनाधिकृत उर्वरक एवं जैविक खाद जप्त, एफआईआर की कार्रवाई

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर बैतूल डॉ सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशानुसार एवं उप संचालक कृषि श्री आर.जी. रजक के मार्गदर्शन एवं समक्ष में दिनांक 26 जून 2026 को जिला स्तरीय उर्वरक निरीक्षण दल द्वारा विकासखंड घोड़ाडोंगरी अंतर्गत कृषि आदान प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान मेसर्स काका बीज भंडार, बागडोना (सारनी) के प्रोपराइटर श्री बजरंग लाल अग्रवाल के स्वयं के अनाधिकृत गोदाम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में गोदाम में मैसर्स मोनि मिनरल्स एंड ग्राइंडर्स (यूनिट-2), औद्योगिक क्षेत्र, मेघनगर (झाबुआ) द्वारा निर्मित एन.पी.के. 20:20:10 उर्वरक की 16 बोरी एवं हक्क्य 12:32:06 उर्वरक की 05 बोरी कुल 21 बोरियां तथा मैसर्स मॉडर्न एग्रो जेनेटिकस लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर-3, पीथमपुर (धार) द्वारा निर्मित उजाला बायो ऑर्गेनिक मैन्योर की 44 बाल्टियां बिना अनुज्ञप्ति में दर्ज कराए अनाधिकृत रूप से भंडारित एवं विक्रय हेतु रखी हुई पाई गईं।

'दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान' का तीसरा चरण 13 जुलाई से

सीहोर (निप्र)। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा 'दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान' चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारी-कर्मचारी पशुपालकों के घर पहुंचेंगे और नस्ल सुधार, पशु पोषण, टीकाकरण एवं सेक्स सॉर्टेड सीमेन के बारे में जानकारी देंगे। तीसरे चरण में 3 से 4 पशु (गौवंश एवं भैंसवंश) रखने वाले पशुपालकों के यहां प्रशिक्षित विभागीय अमले द्वारा घर जाकर भेंट की जाएगी। नस्ल सुधार, पशु पोषण एवं पशु स्वास्थ्य विषय पर जागरुक किया जाएगा। इस चरण में प्रदेश के 5 लाख 72 हजार पशुपालकों के घर जाकर भेंट करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर विभाग द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तृतीय चरण की अवधि 6 दिन निर्धारित की गई है। आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम 9 दिन तक बढ़ाया जा सकेगा। अभियान के दौरान मैदानी अमले की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। उप संचालक, कार्यालय में पदस्थ एवं राज्य स्तर पर प्रशिक्षित कार्यक्रम के नोडल अधिकारी को प्रभारी बनाया जाएगा।अभियान में मंत्री, सांसद, विधायक सहित जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उप संचालक, पशुपालन एवं डेयरी को जनप्रतिनिधियों से व्यक्तिगत भेंट कर उन्हें अभियान से जोड़ने को कहा गया है।

नर्मदापुरम में शराब तस्करों पर आबकारी का दोहरा शिकंजा

17 घंटे में दो कारों से 16 पेटियां जब्त, कट्टा दिखाकर भागा एक आरोपी

नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में रविवार को 17 घंटे के भीतर आबकारी एडीईओ आरपी अहिरवार के नेतृत्व में टीम ने बांद्राभान रोड घानाबढ़ और हरदा रोड एसपीएम गेट नंबर 1 के पास से शराब तस्करी करते दो कार को पकड़ा, जिसमें 16 पेटी शराब मिली। बांद्राभान में आबकारी टीम के खड़े होने की भनक लग जाने से तस्कर अंधेरे में गाड़ी छोड़कर भाग निकले।

वहीं एसपीएम गेट नम्बर 1 के पास गाड़ी पकड़ने के दौरान आबकारी के साथ शराब ठेकेदार के साथ कर्मचारी भी शामिल थे। इस दौरान कुछ दूरी तक पहले पीछा किया गया। गाड़ी में बैठे दो आरोपियों में से एक ने देशी कट्टा (पिस्तौल) भी निकाल दिखाया। फिर गाड़ी रुकते ही आबकारी टीम ने तस्करों को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन झड़प के बाद एक आरोपी मौके से भाग निकला।

दूसरे आरोपी दीपक अहिरवार निवासी नर्मदापुरम को पकड़ लिया। देशी कट्टा सामने आने से रात 10 बजे आबकारी अधिकारी ने 7 पेटी शराब, एक आरोपी, गाड़ी और देशी कट्टा देहात थाना पुलिस को कार्रवाई के लिए सौंपा। मामले में पुलिस ने रविवार सोमवार की दरम्यानी देर रात 1 बजे अवैध शराब तस्करी और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया।

सवालखेड़ा शराब ठेके से लाई गई थी शराब

सहायक आबकारी अधिकारी अहिरवार ने बताया पूछताछ में आरोपी दीपक अहिरवार ने सांवलखेड़ा की शराब दुकान से यह शराब की पेटियों को रखकर लाने की बात कहीं। सफेद रंग की बलेनो गाड़ी को चलाने वाला आरोपी भाग गया है।

नाकाबंदी से 200 मीटर दूर गाड़ी छोड़कर भागे तस्कर : ग्राम बांद्राभान घानाबढ़ हाईवे पर आबकारी टीम के नाकाबंदी कर अवैध शराब पकड़ने की तैयारी में थी। लेकिन तस्करों को इसकी भनक लग जाने से नाकाबंदी से 200 मीटर दूर तस्करों ने गाड़ी मोड़कर शराब की पेटियों से रखी वैगनआर गाड़ी छोड़कर तस्कर भाग निकले।

कुछ देर बाद जब वृत्त प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी आरपी अहिरवार, मुख्य आरक्षक दुर्गाप्रसाद मांझी, रघुवीरप्रसाद निमोदा और आरक्षक सुरेश सिकरिया ने लावारिस खड़ी गाड़ी चेक किया तो उसमें शराब की 17 पेटियां रखी नजर आई। खोलने पर 87 लीटर देसी मदिरा और बीयर बरामद की गई। अज्ञात आरोपी के खिलाफ मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क), 34(2)के तहत प्रकरण कायम कर किया गया।

कलेक्टर श्री बालागुरु के. के निर्देश पर जल पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम

सीहोर (निप्र)। जिले में लगातार हो रही वर्षा और जलस्तर बढ़ने की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर श्री बालागुरु के. के निर्देशानुसार नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जिले के नदी, तालाब, डैम, वॉटरफॉल सहित अन्य जल पर्यटन एवं जोखिमपूर्ण स्थलों पर आमजन की आवाजाही को नियंत्रित करने तथा संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की तैनाती की गई है।

प्रशासन द्वारा संबंधित स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करते हुए कर्मचारियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं। तैनात कर्मचारी नागरिकों को जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में जाने से रोकने के साथ ही उन्हें आवश्यक सुरक्षा संबंधी जानकारी भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रमुख जल पर्यटन स्थलों एवं संवेदनशील स्थानों पर चेतावनी संबंधी फ्लेक्स और सूचना बोर्ड लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से नागरिकों से जलभराव, तेज बहाव एवं गहरे पानी वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की जा रही है।

कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वर्षाकाल के दौरान अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें तथा नदी, तालाब, डैम, वॉटरफॉल एवं अन्य जलाशयों के आसपास अनावश्यक रूप से न जाएं। प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन कर स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित करें।

'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत कान्हावाड़ी में किया पौधरोपण

बैतूल (निप्र)। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा स्वैच्छिकता पर्व अभियान के अंतर्गत ग्राम कान्हावाड़ी में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ग्राम अर्जुनगोंदी में 15 जामुन के पौधों का रोपण किया गया तथा 25 सागौन के पौधों के आसपास सफाई कर संरक्षण के लिए थाले बनाए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं पौधों के संवर्धन के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना रहा।

कार्यक्रम में कान्हावाड़ी के सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र उइके, जिला समन्वयक संतोष सिंह राजपूत, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के जोधा धुर्वे, संजय जी, रामशंकर गोह, देवेंद्र उइके, कुवलाल उइके, मंडराम उइके, अमृतलाल यादव, योगेश यादव, सांवलाल उइके, कानुलाल उइके, दशरथ उइके, राजू यादव, रामकिशोर मरावी, आशा उइके, भैरसा भटेके, ग्राम पंचायत के सचिव, सहसचिव, रोजगार सहायक तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

इसी अवसर पर वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सीमांकन कार्य का भी शुभारंभ किया गया। अर्जुनगोंदी, पिपरी एवं कान्हावाड़ी क्षेत्र के ग्रामीणों ने पैदल भ्रमण कर वन भूमि के सीमांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने पौधों की देखभाल, पर्यावरण संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन का संकल्प लिया।

डिजिटल हुए ब्रह्मचारी:आर्ष गुरुकुल में वैदिक मंत्रों के साथ छात्र सीख रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुर

नर्मदापुरम। आर्ष गुरुकुल में वैदिक शिक्षा के साथ अब आधुनिक तकनीक भी पढ़ाई जा रही है। गुरुकुल में इस साल से छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग सिखाया जा रहा है। परिसर में वाई-फाई लगाया गया है। शिक्षक और प्राचार्य मोबाइल का उपयोग करते हैं, लेकिन छात्रों को मोबाइल रखने की अनुमति नहीं है। छात्र कंप्यूटर कक्ष में एआई और कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेते हैं।

कक्षा 12 के ब्रह्मचारी वीर ने बताया कि रोज एआई और चैटजीपीटी के जरिए सवालों के जवाब और जानकारी लेना सिखाया जाता है। सुदामा आर्य ने कहा कि गूगल सर्च से विषयों पर सामग्री जुटाकर पढ़ाई में मदद मिलती है। आशीष आर्य के अनुसार एआई से फोटो और पेंटिंग एडिटिंग जैसे काम भी समझाए जा रहे हैं। शिक्षक बालकृष्ण दुबे ने बताया कि तकनीकी शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ा गया है।

आर्ष गुरुकुल में दी जाती है वैदिक शिक्षा : आर्ष गुरुकुल में वेद, दर्शन, उपनिषद, योग, पुराण, व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। शिष्य रोज क्लास में ये विषय सीखते हैं। दिनचर्या सुबह 4 बजे शुरू होती है। रोज यज्ञ होता है।

अब धीरे-धीरे आधुनिक और तकनीकी ज्ञान भी सिखाया जा रहा है। गुरुकुल से पढ़कर निकले छात्र वैदिक प्रवक्ता बनते हैं। वे देश-विदेश में प्रवचन देते हैं। वे शिक्षक भी बनते हैं। गुरुकुल मप्र महर्षि पतंजली संस्कृत संस्थान से अटैच है। इससे परीक्षाएं होती हैं।

जम्मू, बिहार के शिष्य भी : प्राचार्य सत्यसिंधु आर्य ने बताया कि जम्मू-कश्मीर, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश से 100 शिष्यों को यहां शिक्षा दी जा रही है। पहले यहां पढ़े शिष्य ऊंचे पदों पर हैं। पवन दवे आर्य दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। धनंजय आर्य बिहार के सासाराम में केंद्रीय विद्यालय में टीचर हैं। गुरुकुल के ऋचस्पति परिव्राजक ने बताया कि शिष्य गुरुकुल में रहकर पढ़ते हैं। परिजन समय-समय पर उत्सव के दौरान आते हैं। जरूरत होने पर शिष्य घर भी जाते हैं।

डेस्क युक्त स्कूल बैग बच्चों के स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में होंगे सहायक : केंद्रीय मंत्री श्री उइके

बैतूल (निप्र)। भारत सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल द्वारा अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के तहत यूनिसेड संस्था के सहयोग से 5 जुलाई को जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल के अटल सभागार में स्कूल बैग विद एजुकेशनल डेस्क वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ आयोजित हुआ।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री एवं बैतूल संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री दुर्गादास उइके, घोड़ाडोंगरी विधायक श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उईके, जिला विकास सलाहकार समिति सदस्य श्री सुधाकर पवार उपस्थित थे। इस अवसर पर भारत सरकार के खान मंत्रालय के नीति सलाहकार तथा राजभाषा समिति के सदस्य अवनीश त्रिपाठी, अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट, जिला शिक्षा अधिकारी पूनम वरकड़े भी उपस्थित थी।

सर्वप्रथम मुख्य अतिथियों ने मां सरस्वती के छायाचित्र समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान मुख्य अतिथियों ने बच्चों को डेस्क युक्त बेग वितरित किए। शेष बचे जिले के 27 हजार 778 बच्चों को स्कूल में डेस्क युक्त स्कूल बैग वितरित किए जाएंगे।

स्कूल बैग विद एजुकेशनल डेस्क वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री उइके ने कहा कि डेस्क युक्त स्कूल बैग बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी और नवाचारपूर्ण पहल है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए डेस्क युक्त स्कूल बैग उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि बच्चे कहीं भी सुविधापूर्वक बैठकर अध्ययन कर सकें।

भारत सरकार के खान मंत्रालय के नीति सलाहकार तथा राजभाषा समिति के सदस्य अवनीश त्रिपाठी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं निपुण भारत कार्यक्रम 2023 के अंतर्गत शिक्षा और स्वास्थ्य को सुदृढ़ और बेहतर बनाने के लिए राज्य और केंद्र स्तर पर बच्चों के लिए कई शैक्षणिक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यूनिसेड संस्था भारत की एक अग्रणी संगठन विकसित भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न आईआईटी के साथ देश भर में सामुदायिक शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए नवाचारों की शुरुआत करते हुए ग्रामीण, वंचित, कमजोर वर्ग के जीवन को बदलने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

वर्षा काल में जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए क्लोरीनेशन अभियान जारी

सीहोर (निप्र)। वर्षा ऋतु के दौरान जलजनित बीमारियों की रोकथाम तथा आम नागरिकों को शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जिले में व्यापक स्तर पर क्लोरीनेशन का कार्य किया जा रहा है।

विभागीय अमला पेयजल स्रोतों, हैंडपंपों तथा जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल का नियमित रूप से क्लोरीनेशन कर रहा है, ताकि पेयजल की गुणवत्ता बनी रहे और नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके।इसके साथ ही विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता की सतत निगरानी भी की जा रही है। इसके लिए पेयजल परीक्षण किट के माध्यम से जल के नमूनों की जांच कर पानी की शुद्धता सुनिश्चित की जा रही है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल का ही उपयोग करें तथा यदि पेयजल की गुणवत्ता को लेकर किसी प्रकार की समस्या दिखाई दे तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

आष्टा में कोटवार दल को मिलेगा पुलिस फोर्स जैसा प्रशिक्षण

कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने की पहल की सराहना, तहसीलदार श्री पगारे के निर्देशन में चल रहा प्रशिक्षण

सीहोर (निप्र)। सीहोर जिले की आष्टा तहसील में ग्रामीण प्रशासन और कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक अभिनव पहल की जा रही है। आष्टा तहसील के कोटवारों को संगठित कर उन्हें पुलिस बल की तर्ज पर प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे प्रशासन और पुलिस का प्रभावी सहयोग कर सकें। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने, आपात परिस्थितियों में त्वरित सहयोग उपलब्ध कराने तथा विभिन्न प्रशासनिक गतिविधियों को अधिक सुव्यवस्थित बनाना है।

आष्टा तहसीलदार श्री रामलाल पगारे के मार्गदर्शन में कोटवार दल को अनुशासन, टीम भावना, सतर्कता और

समन्वय के साथ कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें परेड, अनुशासित संचालन, भीड़ प्रबंधन, प्रशासनिक सहयोग, आपदा की स्थिति में प्राथमिक प्रतिक्रिया तथा विभिन्न परिस्थितियों में जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने की जानकारी दी जा रही है। कोटवारों निर्धारित यूनिफॉर्म एक संगठित दल के रूप में अपनी पहचान स्थापित करेंगे।

प्रशिक्षित कोटवार दल का उपयोग प्रमुख त्योहारों, धार्मिक आयोजनों, मेलों, जुलूसों और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में किया जाएगा। इसके साथ ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, प्रशासनिक अभियानों, शांति व्यवस्था बनाए रखने, भीड़ नियंत्रण तथा अनावश्यक विवादों और तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी यह दल पुलिस एवं प्रशासन के सहयोगी के रूप में सक्रिय भूमिका निभाएगा। आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना संकलन और प्रशासन तक त्वरित जानकारी पहुंचाने का दायित्व भी यह दल निभाएगा।

तहसीलदार श्री रामलाल पगारे ने बताया कि कोटवार ग्रामीण प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण देकर उनकी कार्यक्षमता और उपयोगिता को बढ़ाया जा रहा है, जिससे वे प्रशासन और आमजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर सकें। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने तहसीलदार श्री रामलाल पगारे की इस अभिनव पहल की सराहना करते हुए कहा कि कोटवार शासन-प्रशासन की आधारभूत इकाई हैं। उन्हें व्यवस्थित प्रशिक्षण और अनुशासित कार्यप्रणाली से जोड़ने से प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी तथा विभिन्न अवसरों पर पुलिस और प्रशासन को प्रभावी सहयोग मिलेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणादायक मॉडल सिद्ध हो सकती है।

आदिवासियों ने खुद चंदा कर बना दिया सरकारी स्कूल

- 3 साल से सुन रहे थे कोरा आश्वासन, बोले- इन सालों में एक ईंट तक नहीं रखी
- एमपी के डिंडौरी जिले में सिस्टम की नाकामी की एक अलग तस्वीर

भोपाल। सरकारी दावों और खोखले आश्वासनों से जब मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के आदिवासियों का सब्र टूट गया, तो उन्होंने सिस्टम के भरोसे बैठना छोड़ दिया। जिले के समनापुर ब्लॉक के एक आदिवासी बहुल गांव में ग्रामीणों ने मिलकर खुद ही अपने बच्चों के लिए स्कूल की इमारत खड़ी करने का फैसला कर लिया। इसके लिए न केवल फंड जुटाया गया, बल्कि गांव के पुरुष,

महिलाएं और बुजुर्ग खुद राजमिस्त्री और मजदूर बनकर तगाड़ी-फावड़ा उठाए नजर आ रहे हैं। दरअसल, इस आदिवासी टोले में एकमात्र सरकारी प्राथमिक स्कूल था, जिसे स्कूल शिक्षा विभाग ने तीन साल पहले 'जर्जर और असुरक्षित' घोषित कर जमींदोज कर दिया था। अधिकारियों ने तब जल्द ही नया भवन बनाने का वादा किया था, लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद भी वहां एक ईंट तक नहीं रखी गई।

100 परिवारों ने जोड़े 500-500 रुपये

सरकारी फाइलों में बजट की लेट-लतीफी से बच्चों की पढ़ाई दांव पर लगी देख, इस महीने गांव के करीब 100 परिवारों ने एक आपात बैठक बुलाई। तय हुआ कि हर घर से 500-500 रुपये का योगदान दिया जाएगा ताकि निर्माण सामग्री खरीदी जा सके। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पूरा गांव मिलकर सीमेंट का मसाला तैयार कर रहा है, ईंटें ढो रहा है और स्कूल की नींव तैयार कर रहा है।

प्रशासन को 'गिफ्ट' करेंगे स्कूल

ग्रामीणों का कहना है कि दर्जनों अर्जियां और अफसरों के साथ कई बैठकें बेनतीजा रहने के बाद उन्होंने यह सामूहिक कदम उठाया है। ताज्जुब की बात यह है कि ग्रामीणों ने तय किया है कि वे स्कूल तैयार होने के बाद इसे जिला प्रशासन को 'गिफ्ट' कर देंगे ताकि वहां शिक्षक भेजे जा सकें। उधर, इस पूरे मामले पर जिला परियोजना समन्वयक (DPC) दिवाकर तिवारी ने ग्रामीणों के गुस्से को जायज ठहराया है। उन्होंने दबी जुबान में अपनी लाचारी कबूल करते हुए कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग को अभी तक स्कूल के पुनर्निर्माण के लिए जरूरी फंड ही प्राप्त नहीं हुआ है।

भोपाल-राजगढ़ को जोड़ने वाला वैकल्पिक मार्ग बंद

बैरसिया-नरसिंहगढ़ के बीच पार्वती नदी पर बना है मार्ग; जलस्तर बढ़ने से रोक

भोपाल। भोपाल और राजगढ़ जिले को जोड़ने वाले पार्वती नदी के अस्थायी वैकल्पिक मार्ग से गुजरने पर रोक लगा दी गई है। सोमवार देर रात बैरसिया एसडीएम आशुतोष शर्मा ने यह आदेश जारी किए। नदी में जल स्तर बढ़ने की वजह से यह फैसला लिया गया। एसडीएम शर्मा के आदेश में लिखा है कि बारिश के कारण पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इससे बैरसिया-नरसिंहगढ़ मार्ग पर नदी के मध्य निर्मित अस्थायी वैकल्पिक मार्ग जलमग्न हो गया है। तेज बहाव के कारण आवागमन अत्यंत जोखिमपूर्ण है। इसलिए आवागमन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। एसडीएम ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र में आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड एवं सुरक्षा संकेतक स्थापित किए जाएं। ताकि कोई भी व्यक्ति जोखिम उठाकर मार्ग का उपयोग न कर सके।

तहसीलदार, पुलिस को जिम्मा- आदेश के पालन के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जनपद पंचायत, पीडब्ल्यूडी और पुलिस विभाग के अधिकारियों को सतत निगरानी रखने और आवश्यकता अनुसार सुरक्षा बल तैनात कर नागरिकों को सुरक्षित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जो आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 तथा अन्य प्रचलित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

वैकल्पिक रास्ते में पानी, इसलिए वाहन फंस रहे

साल 1976 में रुनाहा से नरसिंहगढ़ तक सड़क MPRDC यानी मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने बनाई थी। वहीं, ब्रिज पीडब्ल्यूडी ने बनाया था। 17 जनवरी 2025 को ब्रिज एक जगह से धंस गया था। एहतियातन बैरसिया एसडीएम शर्मा ने ब्रिज से आने-जाने पर रोक लगा दी थी। कुछ दिन बाद स्टॉपडैम से पानी खाली कर डायवर्सन रूट तैयार किया गया था। बारिश से पहले तक इसी रूट से बस, ट्रक समेत चार पहिया और टू-व्हीलर गुजर रहे थे, लेकिन पानी बढ़ गया है। बावजूद कई वाहन चालक खतरा लेते हुए इसके ऊपर से गुजर रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में एक बस तिरछी हो गई थी। इसे जैसे-तैसे निकाला तो एक दिन पहले ही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली सड़क से स्टॉपडैम के पानी में गिर गई। ट्रैक्टर में चार लोग सवार थे, जो बच गए।

नेशनल हाईवे से जोड़ता है ब्रिज

बैरसिया-नरसिंहगढ़ रोड पर बना यह ब्रिज मेघरा नवीन गांव में है। यह भोपाल जिले का गांव है जबकि दूसरी तरफ राजगढ़ जिले का बरायठा गांव है। भोपाल, राजगढ़ के अलावा गुना, विदिशा, शिवपुरी, अशोकनगर, आगर-मालवा, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन आने-जाने के लिए भी ब्रिज का उपयोग किया जाता है। जब ब्रिज ठीक था, तब एक दिन में डेढ़ से 2 लाख तक लोग गुजरते थे। वर्तमान में 8 से 10 हजार लोग गुजर रहे हैं। यह ब्रिज आगरा-बंबई राष्ट्रीय राजमार्ग को भी जोड़ता है। करीब 49 साल पुराने ब्रिज की आखिरी बार मरम्मत साल 2019-20 में की गई थी। इसके पहले भी एक बार मरम्मत की गई थी। मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से ब्रिज जर्जर हालत में पहुंच गया था।

हिरणों के झुंड के पीछे पड़ गया आवारा कुत्ता

कुएं में गिर गए सब, एक साथ 13 बेजुबानों की मौत

शाजापुर। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले का कालापीपल क्षेत्र रविवार को उस समय दहल उठा, जब एक ही खेत के कुएं से 13 हिरणों और एक आवारा कुत्ते के सड़ चुके शव बरामद हुए। खरदौनकलां गांव के एक खेत में स्थित कुएं से जब अचानक असहनीय दुर्गंध आने लगी, तो खेत मालिक कीटनाशक का छिड़काव करने पहुंचे थे। कुएं के भीतर का खौफनाक मंजर देखकर उनके होश उड़ गए और तुरंत पुलिस व वन विभाग को सूचना दी गई। शुरुआती जांच और वन्यजीव विशेषज्ञों के मुताबिक, यह भीषण हादसा दो से तीन दिन पुराना है। माना जा रहा है कि हिरणों का एक बड़ा झुंड आवारा कुत्ते से अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भाग रहा था। इसी दौरान कुएं की मुंडेर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के कारण पूरा झुंड एक के बाद एक कुएं में समा गया, और उनका पीछा कर रहा कुत्ता भी उसी में गिरकर मर गया।

करोड़ों के 'हेलीकॉप्टर रेस्क्यू' पर उठे सवाल- इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले हिरणों में 4 नर और 9 मादा शामिल हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित प्राणी होने के कारण, नायब तहसीलदार की कड़ी निगरानी में शवों को बाहर निकाला गया। डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्ट्म कराने के बाद मौके पर ही सभी का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

करोड़ों का बजट और जमीनी हकीकत: इस घटना ने शाजापुर में वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग की कलई खोल दी है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ महीने पहले ही इसी कालापीपल क्षेत्र से किसानों की फसलों को बचाने के लिए वन विभाग ने 'हंक पद्धति' से करोड़ों रुपये खर्च कर हेलीकॉप्टर के जरिए हिरणों और नीलगायों को रेस्क्यू किया था। उन्हें प्रदेश के अन्य अभ्यारण्यों में शिफ्ट किया गया था, लेकिन इस हादसे ने साफ कर दिया है कि जमीनी स्तर पर निगरानी अब भी शून्य है। सड़क हादसों के बाद अब खेतों के असुरक्षित कुएं बेजुबानों के लिए काल बन रहे हैं, जिससे स्थानीय ग्रामीणों और पर्यावरणविदों में भारी आक्रोश है।

सीबीआई की बड़ी जीत, कोर्ट ने कहा-पासवर्ड बताएं

समर्थ के लैपटॉप का वॉयस सैंपल से खुलेगा सीक्रेट

भोपाल। ट्विशा शर्मा की रहस्यमयी मौत के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को एक बेहद कड़ा और अहम फैसला सुनाया है। विशेष सीबीआई अदालत की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) शोभना भालावे ने जांच एजेंसी की उस अर्जी को हरी झंडी दे दी है, जिसमें आरोपी पक्ष के वॉयस सैंपल और डिजिटल सबूतों को खंगालने की अनुमति मांगी गई थी। इस आदेश के बाद अब आरोपी वकील समर्थ सिंह को अपने लैपटॉप का पासवर्ड सीबीआई को सौंपना होगा। इसके साथ ही, समर्थ सिंह और उनकी मां, पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह को अपनी आवाज के नमूने भी जांच एजेंसी को देने होंगे, जिससे इस रहस्यमयी मौत से जुड़े कई बड़े राज उजागर होने की उम्मीद है।

पूर्व जज की आपत्ति कोर्ट ने की खारिज- अदालती कार्यवाही के दौरान पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह ने सीबीआई की इस मांग पर तीखी आपत्ति जताई थी। उन्होंने मांग की थी कि जांच एजेंसी पहले यह स्पष्ट करे कि उन्हें वॉयस सैंपल की जरूरत क्यों है और इसके पीछे क्या पुख्ता आधार है। हालांकि, कोर्ट ने पूर्व जज की इस दलील को

सिरे से खारिज कर दिया। इसके साथ ही, अदालत ने आरोपियों द्वारा दायर उन अर्जियों को भी कूड़ेदान में डाल दिया, जिसमें दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीएफएसएल रिपोर्ट और मृतका ट्विशा शर्मा के वित्तीय दस्तावेजों को सौंपने की मांग की गई थी।

चोरी की शिकायत पर भी झटका- पूर्व जज गिरिबाला सिंह को अदालत से एक और झटका लगा। उन्होंने अपने आवास पर कथित चोरी को लेकर अदालत से कार्रवाई की गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह एक अलग मामला है जो पहले से ही कटारा हिल्स थाने में दर्ज है, इसलिए इसे इस केस से नहीं जोड़ा जा सकता। अदालत ने अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। इस दिन सीबीआई को अपनी फाइनल स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी होगी। साथ ही, मृतका के परिवार द्वारा दायर अर्जियों पर भारत सरकार और एम्स दिल्ली को भी अदालत में अपना जवाब दाखिल करना है।

एमपी के 22 खिलाड़ी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई

टीटी नगर स्टेडियम में खिलाड़ियों से मिले मंत्री विश्वास सारंग

भोपाल। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने मंगलवार को टी.टी. नगर स्टेडियम में आगामी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से आत्मीय संवाद कर उनकी तैयारियों, प्रशिक्षण, फिटनेस और आगामी प्रतियोगिताओं को लेकर विस्तार से चर्चा की तथा उन्हें शुभकामनाएं देते हुए पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ देश का प्रतिनिधित्व करने का आह्वान किया।

विश्वास सारंग ने कहा-अंतरराष्ट्रीय मंच पर एमपी इतिहास रचेगा

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि एशियन गेम्स जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों का बड़ी संख्या में चयन होना पूरे प्रदेश के लिए गर्व और सम्मान का विषय है। यह उपलब्धि खिलाड़ियों के अथक परिश्रम, प्रशिक्षकों के समर्पण तथा प्रदेश सरकार द्वारा खेलों के विकास के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आज मध्यप्रदेश देश के अग्रणी खेल राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है और यहां के खिलाड़ी लगातार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं।

प्रदेश सरकार खेलों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। खिलाड़ियों को आधुनिक खेल अधोसंरचना, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, वैज्ञानिक कोचिंग, खेल विज्ञान, पोषण, आवास एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। सरकार की प्राथमिकता है कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हर स्तर पर आवश्यक सहयोग और अवसर प्राप्त हों। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि एशियन गेम्स केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि देश के लिए गौरव अर्जित करने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्हें पूरा विश्वास है कि मध्यप्रदेश के खिलाड़ी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारत के लिए अधिक से अधिक पदक जीतेंगे और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि वे अनुशासन, समर्पण और सकारात्मक सोच के साथ अपनी तैयारियां जारी रखें। पूरे प्रदेश की शुभकामनाएं और विश्वास उनके साथ हैं। उन्होंने प्रशिक्षकों और खेल विभाग के अधिकारियों की भी सराहना करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन और समर्पण का ही परिणाम है कि मध्यप्रदेश के खिलाड़ी लगातार नई सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि आगामी एशियन गेम्स के लिए मध्यप्रदेश के 22 खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल विधाओं में क्वालिफाई किया है। इनमें एथलेटिक्स, शूटिंग, रायफल, कैनो स्लालम, कैनोइंग, कायाक, शॉटगन, क्लाउड जूडो, घुड़सवारी सहित विभिन्न खेलों के खिलाड़ी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों से प्रदेश को उत्कृष्ट प्रदर्शन और पदक जीतने की बड़ी उम्मीदें हैं। इस अवसर पर खेल विभाग के सचिव श्री संजीव सिंह, संचालक श्री अंशुमन यादव, उपसचिव श्री अजय श्रीवास्तव, खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, प्रशिक्षक, खेल अकादमियों के प्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे। मंत्री श्री सारंग ने सभी चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पूरा मध्यप्रदेश उनके साथ खड़ा है और उन्हें विश्वास है कि वे अपने प्रदर्शन से देश और प्रदेश को गौरवान्वित करेंगे।

नवनियुक्त इंजीनियरों को पॉवर प्लांट निर्माण का मिला प्रशिक्षण

भोपाल। मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के नवनियुक्त 10 कनिष्ठ अभियंताओं (सिविल) का छह सप्ताह का विशेष तकनीकी प्रशिक्षण राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, नागपुर में आयोजित किया गया। अभियंताओं को ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण, संधारण तथा आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग तकनीकों का गहन सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। छह सप्ताह तक चले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य नवनियुक्त अभियंताओं को विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की वास्तविक कार्यप्रणाली से परिचित कराते हुए उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना था। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों जैसे कंक्रीट टेक्नोलॉजी, मटेरियल टेस्टिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, कार्य मापन, निर्माण पर्यवेक्षण तथा नवीनतम इंजीनियरिंग तकनीकों के अनुप्रयोग की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण का प्रमुख आकर्षण महाराष्ट्र के चंद्रपुर और कोराडी स्थित 2×600 मेगावाट सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत इकाइयों का औद्योगिक भ्रमण रहा। इस दौरान प्रशिक्षु अभियंताओं ने निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं में फाउंडेशन, संरचनात्मक निर्माण एवं परियोजना निष्पादन की प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन कर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया।